



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-15072026-274504
CG-MH-E-15072026-274504

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 453]
No. 453]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 2026/आषाढ 23, 1948
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 14, 2026/ASHADHA 23, 1948

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

अधिसूचना

मुंबई, 14 जुलाई, 2026

संदर्भ: HO:HRM:118:1324 .— बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निदेशक मंडल ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श तथा केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के पत्र संख्या 4/2/1/2022-आईआर, दिनांक 13 मार्च, 2024 के अनुसरण में की गयी या करने से छोड़ी गई बातों को छोड़कर 1 नवंबर, 2022 से इस अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख तक बैंक ऑफ़ बड़ौदा (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाए हैं, अर्थात्:-

- (1) इन विनियमों को बैंक ऑफ़ बड़ौदा (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जाएगा।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
- बैंक ऑफ़ बड़ौदा (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 (जिसे आगे उक्त विनियमन कहा जाएगा) ये विनियम 3 के, खंड (एफ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(एफ) चिकित्सा सुविधाओं और अवकाश किराया रियायत के प्रयोजन के लिए एक अधिकारी कर्मचारी के ‘परिवार’ से अभिप्राय है:

- (i) अधिकारी कर्मचारी की पत्नी/ पति;
- (ii) पूर्ण रूप से आश्रित अविवाहित बच्चे (जिसमें सौतेले एवं कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे भी शामिल हैं);
- (iii) 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता वाले शारीरिक या मानसिक दिव्यांग भाई या बहन जो पूर्ण रूप से आश्रित हैं;
- (iv) विधवा पुत्री और आश्रित तलाकशुदा या अलग रह रही पुत्री;
- (v) बहन जो अविवाहित हो या तलाकशुदा या परित्यक्ता हो या पति से अलग हो या विधवा बहनें;
- (vi) कर्मचारी पर पूरी तरह से आश्रित माता-पिता:

बशर्ते कि शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के मामले में, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, उन्हें उनकी शादी के बाद भी आश्रित के रूप में माना जाएगा, बशर्ते कि वे आश्रित के लिए आय मानदंडों को पूरा करते हों।

स्पष्टीकरण 1.- “पूर्ण रूप से आश्रित परिवार के सदस्य” का अभिप्राय परिवार के ऐसे सदस्य से है जिसकी मासिक आय ₹18,000/- से अधिक न हो और यदि माता-पिता में से किसी एक की मासिक आय ₹18,000/- से अधिक है या माता-पिता दोनों की सकल मासिक आय ₹18,000/- से अधिक है तो माता-पिता दोनों अधिकारी कर्मचारी पर पूर्ण रूप से आश्रित नहीं माने जाएंगे।

स्पष्टीकरण 2. -चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति योजना और अवकाश किराया रियायत के प्रयोजन के लिए सभी अधिकारी कर्मचारियों के लिए आश्रित माता-पिता या सास-ससुर में से किन्हीं दो को कवर किया जाएगा। अधिकारी कर्मचारी के पास एक कैलेंडर वर्ष में एक बार आश्रितों में से किसी एक या दोनों को प्रतिस्थापित करने का विकल्प होगा।

स्पष्टीकरण 3. - यह परिभाषा 1 अप्रैल, 2024 से और कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए, चिकित्सा बीमा योजना के उद्देश्य से प्रभावी होगी और आश्रितों के लिए संशोधित मासिक आय मानदंड 1 नवंबर, 2024 से प्रभावी होंगे।”

3. उक्त विनियमों के विनियमन 4 में,-

(ए) उप-विनियमन (7) के स्पष्टीकरण को हटा दिया जाएगा;

(बी) उप-विनियमों 9 और 10 के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमन प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(9) 1 नवंबर, 2022 और उसके बाद से प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होंगे:

(ए) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी

वेतनमान VIII = ₹ 253000 - 9000/4 - 289000

वेतनमान VII = ₹ 156500 - 4340/4 - 173860

वेतनमान VI = ₹ 140500 - 4000/4 - 156500

(बी) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान V = ₹ 120940 – 3360/2 – 127660 – 3680/2 – 135020

वेतनमान IV = ₹ 102300 – 2980/4 – 114220– 3360/2 – 120940

(सी) मध्य प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान III = ₹ 85920-2680/5– 99320 – 2980/2 – 105280

वेतनमान II = ₹ 64820–2340/1 – 67160 –2680/10 – 93960

(डी) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी:

वेतनमान I = ₹ 48480-2000/7- 62480-2340/2-67160-2680/7-85920.

स्पष्टीकरण.- 31 अक्तूबर, 2022 को प्रभावी वेतनमान जिस अधिकारी पर भी लागू होते हैं उसे 01 नवंबर, 2022 को इस उप विनियम के अनुसार चरणवार निर्धारित वेतनमान में नियत किया जाएगा अर्थात् संबंधित वेतनमान में प्रथम चरण से तदनुरूप चरण पर और वेतनवृद्धि सामान्यतः वर्ष पूर्ण होने की तिथि पर ही देय होगी, बशर्ते जहां अन्यथा न हो।

(10) उप विनियमन (1) से (9) में उल्लिखित किसी भी बात का आशय यह नहीं होगा कि बैंक पूरे समय इन श्रेणियों में अधिकारियों को सेवारत रखने के लिए बाध्य है।

(11) 1 नवंबर, 2012 और उसके बाद से अधिकारियों को विशेष भत्ते का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:

वेतनमान श्रेणी I-III - मूल वेतन का 7.75 प्रतिशत + उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान श्रेणी IV-V- मूल वेतन का 10 प्रतिशत + उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान श्रेणी VI-VII- मूल वेतन का 11 प्रतिशत + उस पर लागू महंगाई भत्ता

(12) 1 नवंबर, 2017 और उसके बाद से अधिकारियों को विशेष भत्ते का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:

वेतनमान श्रेणी I-III - मूल वेतन का 16.40 प्रतिशत + उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान श्रेणी IV-V- मूल वेतन का 19 प्रतिशत + उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान श्रेणी VI-VIII- मूल वेतन का 20 प्रतिशत + उस पर लागू महंगाई भत्ता

बशर्ते कि वेतनमान श्रेणी VIII में अधिकारी 31 मार्च, 2020 से विशेष भत्ते के लिए पात्र होंगे।

(13) 1 नवंबर, 2022 और उसके बाद से अधिकारियों को विशेष भत्ते का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:

वेतनमान श्रेणी I - मूल वेतन का 26.50 प्रतिशत + उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान श्रेणी II-III - मूल वेतन का 28.30 प्रतिशत + उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान श्रेणी IV-V - मूल वेतन का 30.50 प्रतिशत + उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान श्रेणी VI-VII - मूल वेतन का 31.50 प्रतिशत + उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान श्रेणी VIII - मूल वेतन का 28.30 प्रतिशत + उस पर लागू महंगाई भत्ता

नोट: लागू महंगाई भत्ते के साथ उप-विनियम (11) से (13) में निर्दिष्ट विशेष भत्ते को अधिवर्षिता लाभ अर्थात् परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली (नई पेंशन योजना), भविष्य निधि और ग्रेच्युटी सहित पेंशन के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा।

4. कथित विनियम के विनियमन 5 में, -

(ए) उप-विनियमन (1) के लिए निम्नलिखित उप-विनियमन प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

"(1) दिनांक 01 नवंबर, 2022 और उसके बाद से विनियम 4 के उप विनियम (9) के प्रावधानों के अधीन वेतनवृद्धियाँ निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूर की जाएंगी, अर्थात्:-

(ए) विनियम 4 के उप विनियम (9) में वर्णित विभिन्न वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धियाँ, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन वार्षिक आधार पर देय होंगी और जिस माह में यह देय होंगी उस माह की पहली तारीख को दी जाएंगी;

(बी) वेतनमान I और वेतनमान II के अधिकारियों को अपने संबंधित वेतनमान में अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के एक साल बाद खंड (सी) एवं (डी) में निर्दिष्ट अनुसार अगले उच्च वेतनमान में अवरुद्ध वेतनवृद्धि सहित वेतन वृद्धि दी जाएगी बशर्ते कि उन्होंने अपनी पात्रता सीमा को पार कर लिया हो;

(सी) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I का अधिकारी जो विनियम (बी) के अनुरूप अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के पश्चात मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II में पहुंच चुका है, वह प्रत्येक 2 वर्षों की सेवा पूरी होने पर सात अवरुद्ध वेतनवृद्धियों के लिए पात्र होगा जिनमें से पहली दो ₹2680/- तथा उसके बाद की पाँच ₹2980/- की होंगी:

बशर्ते कि अधिकारी पाँचवीं अवरुद्ध वेतनवृद्धि जारी किए जाने के दो साल बाद या 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, छठवीं अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा।

बशर्ते कि अधिकारी पाँचवीं अवरुद्ध वेतनवृद्धि जारी किए जाने के चार साल बाद या 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, सातवीं अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा।

(डी) मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान-II का अधिकारी जो विनियम (बी) के अनुरूप अधिकतम वेतनमान तक पहुँचने के पश्चात मध्य प्रबंधन श्रेणी-III के वेतनमान में पहुँच चुका है वह प्रत्येक दो साल की सेवा पूरी करने पर ₹2980/- (प्रत्येक) की सात अवरुद्ध वेतनवृद्धियों के लिए पात्र होगा:-

बशर्ते कि अधिकारी पाँचवीं अवरुद्ध वेतनवृद्धि जारी किए जाने के दो साल बाद या 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, छठवीं अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा।

बशर्ते कि अधिकारी पाँचवीं अवरुद्ध वेतनवृद्धि जारी किए जाने के चार साल बाद या 1 नवंबर 2022, जो भी बाद में हो, सातवीं अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

(ई) मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III में अधिकारीगण अर्थात् जो मध्य प्रबंधन श्रेणी/वेतनमान III में भर्ती हुए हैं अथवा पदोन्नत हुए हैं, अधिकतम वेतनवृद्धि तक पहुंचने के बाद प्रत्येक दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर आठ अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से पहली चार अवरुद्ध वेतनवृद्धियां प्रत्येक के लिए ₹2980/- और अगली चार अवरुद्ध वेतनवृद्धियां ₹3360/- प्रत्येक की होंगी:

बशर्ते कि अधिकारी छठवीं अवरुद्ध वेतनवृद्धि जारी होने के दो साल बाद या 01.11.2022 को, जो भी बाद में हो, सातवीं अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

बशर्ते कि छठी अवरुद्ध वेतनवृद्धि जारी होने के चार साल बाद या 01.11.2022 को, जो भी बाद में हो, आठवीं अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

(एफ) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान IV के अधिकारी अधिकतम वेतनवृद्धि तक पहुंचने के बाद प्रत्येक दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पांच अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से पहली अवरुद्ध वेतनवृद्धि ₹3660/- की होगी और अगली चार अवरुद्ध वेतनवृद्धि ₹3680/- प्रत्येक की होगी:

बशर्ते कि अधिकारी दूसरी अवरुद्ध वेतनवृद्धि के दो साल बाद या 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, तीसरी अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

बशर्ते कि अधिकारी दूसरी अवरुद्ध वेतनवृद्धि के चार साल बाद या 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, चौथी अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

बशर्ते कि अधिकारी दूसरी अवरुद्ध वेतनवृद्धि के छह साल बाद या 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, पाँचवीं अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

(जी) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान V के अधिकारी अधिकतम वेतनवृद्धि तक पहुंचने के पश्चात प्रत्येक 2 वर्ष पूर्ण होने पर, ₹4000/- की चार अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते कि अधिकारी अधिकतम वेतनवृद्धि तक पहुंचने के चार साल बाद या 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, दूसरी अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

बशर्ते कि अधिकारी अधिकतम वेतनवृद्धि तक पहुंचने के छह साल बाद या 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, तीसरी अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

बशर्ते कि अधिकारी अधिकतम वेतनवृद्धि तक पहुंचने के आठ साल बाद या 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, चौथी अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

(एच) उच्च प्रबंधन वेतनमान VI के अधिकारी अधिकतम वेतनवृद्धि तक पहुंचने के बाद प्रत्येक दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर तीन अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से पहली दो अवरुद्ध वेतनवृद्धि ₹4000/- प्रत्येक की होगी और तीसरी अवरुद्ध वेतनवृद्धि ₹4340/- की होगी:

बशर्ते कि अधिकारी जो पहले ही अधिकतम वेतनवृद्धि तक पहुँच चुका हो वह अधिकतम वेतनवृद्धि तक पहुँचने के दो साल बाद या 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, ₹4000/- की पहली अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

बशर्ते कि अधिकारी जो पहले ही अधिकतम वेतनवृद्धि तक पहुँच चुका हो वह अधिकतम वेतनवृद्धि तक पहुँचने के चार साल बाद या 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, ₹4000/- की दूसरी अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

बशर्ते कि अधिकारी जो पहले ही अधिकतम वेतनवृद्धि तक पहुँच चुका हो वह अधिकतम वेतनवृद्धि तक पहुँचने के छह साल बाद या 1 नवंबर 2022 को, जो भी बाद में हो, ₹4340/- की तीसरी अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

(आई) उच्च प्रबंधन वेतनमान VII के अधिकारी अधिकतम वेतनवृद्धि तक पहुंचने के बाद प्रत्येक दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ₹4340/- प्रत्येक की तीन अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा:

बशर्ते कि अधिकारी जो पहले ही अधिकतम वेतनवृद्धि तक पहुँच चुका हो वह अधिकतम वेतनवृद्धि तक पहुँचने के दो साल बाद या 1 नवंबर 2022, जो भी बाद में हो, पहली अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते कि अधिकारी जो पहले ही अधिकतम वेतनवृद्धि तक पहुँच चुका हो वह अधिकतम वेतनवृद्धि तक पहुँचने के चार साल बाद या 1 नवंबर 2022, जो भी बाद में हो, द्वितीय अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते कि अधिकारी जो पहले ही अधिकतम वेतनवृद्धि तक पहुँच चुका हो वह अधिकतम वेतनवृद्धि तक पहुँचने के छह साल बाद या 1 नवंबर 2022, जो भी बाद में हो, तीसरी अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे;

नोट: इस उप-विनियमन के खंड (ए) से (आई) में उल्लिखित वेतन वृद्धि की अनुमति उस अधिकारी को नहीं दी जाएगी जिसने पदोन्नति ऑफर को स्वीकार करने से मना कर दिया हो।

स्पष्टीकरण :- इस उप-विनियमन के तहत अगले उच्च वेतनमान में ऐसी वेतनवृद्धि की मंजूरी का आशय पदोन्नति नहीं है और अधिकारियों के विशेषाधिकार, परिलब्धियाँ, कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ उनके मूल पदों के अनुरूप ही जारी रहेंगी।";

(बी) उप- विनियम (2) में-

(i) स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित परंतुक डाला जाएगा, जो निम्नानुसार है: -

"बशर्ते कि 1 नवंबर, 2022 को और उसके बाद से, सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स परीक्षा (सीएआईआईबी-II) के भाग II को पूरा करने वाले अधिकारी अपने वेतनमान में दो वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे, इसके अलावा भारतीय बैंकर्स संस्थान के संस्थान की परीक्षा (जेएआईआईबी) के जूनियर एसोसिएट या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स परीक्षा (सीएआईआईबी-I) के सर्टिफाइड एसोसिएट के भाग I को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते कि वे अधिकारी जो दिनांक 1 नवंबर, 2022 को बैंक की सेवा में थे और जिन्होंने पहले ही सीएआईआईबी-II परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, वे 1 नवंबर, 2022 से अथवा सीएआईआईबी-II उत्तीर्ण करने की तारीख से जो भी बाद में हो, दूसरी अतिरिक्त वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते यह भी कि यदि कोई अधिकारी 8 मार्च, 2024 की स्थिति में, वेतनमान के शीर्ष पर पहुँचने के बाद (जेएआईआईबी या सीएआईआईबी के मामले में) अथवा वेतनमान के शीर्ष से एक चरण पहले तक पहुँचने के बाद पहले ही जेएआईआईबी या सीएआईआईबी-I या सीएआईआईबी (सीएआईआईबी-II) परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है अथवा करता है और जेएआईआईबी अथवा सीएआईआईबी-I या सीएआईआईबी-II के मामले में उसे ऐसी पात्रता अर्जित करने के बावजूद भी, संबंधित कर्मचारियों के वेतनमान में कोई वेतनवृद्धि शेष न होने के कारण, जिन कर्मचारियों को देय वेतनवृद्धियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं, तो ऐसे मामलों में संबंधित कर्मचारियों के वेतनमान में देय अवरुद्ध वेतनवृद्धि को, एक वर्ष या दो वर्ष, जैसा भी मामला हो आगे बढ़ाया जा सकेगा।"

(ii) खंड (एच) के बाद स्पष्टीकरण में, तथा टिप्पणी (नोट) से पूर्व, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"(i) 1 नवंबर, 2022 और उसके बाद से, अन्य सभी बातें समान रहने पर, व्यावसायिक योग्यता वेतन की राशि को निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट अनुसार संशोधित माना जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

जिन्होंने भारतीय बैंक्स संस्थान की जूनियर एसोसिएट (जेएआईआईबी) अथवा भारतीय बैंक्स संस्थान का प्रमाणित एसोसिएट - भाग I (सीएआईआईबी-I) परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है	वेतनमान के शीर्ष पर पहुँचने के एक वर्ष बाद ₹1370/- प्रति माह
वह अधिकारी जिन्होंने भारतीय बैंक्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट (सीएआईआईबी) के दोनों भाग उत्तीर्ण किए हैं	1. वेतनमान के शीर्ष पर पहुँचने के एक वर्ष बाद ₹1370/- प्रति माह 2. वेतनमान के शीर्ष पर पहुँचने के दो वर्ष बाद ₹3425/- प्रति माह 3. वेतनमान के शीर्ष पर पहुँचने के तीन वर्ष बाद ₹5480/- प्रति माह

बशर्ते कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक्स के जूनियर एसोसिएट अथवा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक्स के सर्टिफाइड एसोसिएट (एक या दोनों भाग) की योग्यता अर्जित करने वाले किसी अधिकारी कर्मचारी को वेतनमान के शीर्ष पर पहुँचने के बाद ऐसी योग्यता प्राप्त करने की तारीख से व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त प्रदान की जाएगी तथा व्यावसायिक योग्यता वेतन की बाद की किस्तों का भुगतान व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त के भुगतान की तारीख के संदर्भ के आधार पर किया जाएगा:

बशर्ते यह भी कि 1 नवंबर, 2022 से वेतनमान-VIII में कार्यरत किसी अधिकारी कर्मचारी को कोई भी व्यावसायिक योग्यता वेतन देय नहीं होगा”;

(iii) खंड (v) के बाद, नोट में, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

“(vi) वे अधिकारी जो 1 नवंबर, 2022 को बैंक की सेवा में थे और जिन्होंने पहले ही जेएआईआईबी / सीएआईआईबी / सीएआईआईबी-II पूर्ण कर लिया है तथा व्यावसायिक योग्यता वेतन-II प्राप्त कर रहे हैं, वे व्यावसायिक योग्यता वेतनमान-II के जारी होने की तारीख से एक वर्ष बाद अथवा 1 नवंबर, 2022 और उसके बाद से (जो भी बाद में हो) व्यावसायिक योग्यता वेतनमान-III के लिए पात्र होंगे।

(vii) वे अधिकारी जिन्होंने जेएआईआईबी (सीएआईआईबी-I) अथवा सीएआईआईबी (सीएआईआईबी-II) पूर्ण कर लिया है तथा जो 1 नवंबर, 2022 को या उससे पहले वेतनमान के शीर्ष पर पहुँच चुके हैं और जिन्हें 1 नवंबर, 2022 या उसके पहले पहली अवरूद्ध वेतनवृद्धि प्राप्त नहीं हुई है, वे 1 नवंबर, 2022 को और उसके बाद से व्यावसायिक योग्यता वेतन-I के लिए पात्र होंगे तथा व्यावसायिक योग्यता वेतन की बाद की किस्तों का निर्गमन, इस खंड के अंतर्गत व्यावसायिक योग्यता वेतनमान-I जारी किए जाने की तारीख के संदर्भ के आधार पर किया जाएगा”;

(सी) उप-विनियम (3) में, —

(i) खंड (जी) के बाद के नोट को हटाया जाएगा;

(ii) खंड (एच) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

“(i) 1 नवंबर, 2022 और उसके बाद से, अन्य सभी बातें समान रहने पर, मकान किराया भत्ता सहित नियत वैयक्तिक वेतन को निम्नलिखित दरों पर देय होगा और यह सेवा की संपूर्ण अवधि के लिए नियत (फ्रीज़) रहेगा: -

तालिका

वेतनवृद्धि घटक (₹)	1 नवंबर, 2022 को वेतनवृद्धि घटक पर देय महंगाई भत्ता (₹)	बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराए जाने की स्थिति में देय कुल नियत वैयक्तिक वेतन (₹)
(1)	(2)	(3)
2680	200	2880
2980	222	3202
3360	250	3610
3680	274	3954
4000	298	4298
4340	323	4663
9000	669	9669

नोट:

(i) इस उप-विनियम के खंड (बी), (सी), (डी), (ई), (एफ), (जी), (एच) एवं (आई) की तालिकाओं के कॉलम (3) में दर्शाए अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ता अथवा नियत वैयक्तिक वेतन, केवल उन अधिकारी कर्मचारियों को देय होगा जिन्हें बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराया गया है।

(ii) जो अधिकारी मकान किराया भत्ता हेतु पात्र हैं, उनके लिए नियत वैयक्तिक भत्ता अथवा नियत वैयक्तिक वेतन, खंड(i) के अंतर्गत उपर्युक्त तालिका के कॉलम (1) एवं (2) के अंतर्गत निर्दिष्ट कुल राशि तथा संबंधित अधिकारी द्वारा विनियम 4 के उप-विनियम (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) एवं (9) में निर्धारित संबंधित वेतनमान की अंतिम अर्जित वेतनवृद्धि के आधार पर आहरित मकान किराया भत्ता का योग होगा;

(iii) केवल वे अधिकारी, जो 1 नवंबर, 1993 को अथवा उससे पूर्व बैंक की सेवा में थे, जिस वेतनमान में वे कार्यरत हैं, उसके शीर्ष पर पहुँचने के एक वर्ष बाद नियत वैयक्तिक वेतन के लिए पात्र होंगे।

(iv) 1 नवंबर, 1999 को और उसके बाद से, नियत वैयक्तिक वेतन जारी करने से संबंधित उप-विनियम (2) की स्पष्टीकरण के खंड (सी) में उल्लिखित व्यावसायिक योग्यता वेतन जारी करने के शेड्यूल में कोई परिवर्तन नहीं होगा:

बशर्ते कि, यदि पूर्ववर्ती प्रावधानों के कारण व्यावसायिक योग्यता वेतन की किसी किस्त को एक वर्ष आगे बढ़ा दिया गया है और उसे 1 नवंबर, 1999 को या उसके पश्चात जारी किया जाना निर्धारित है, तो वह किस्त अधिकारी को उसी तारीख से देय होगी तथा यदि कोई दूसरी किस्त देय हो, तो उसका निर्गमन 1 नवंबर, 2000 को किया जाएगा।

(v) नियत वैयक्तिक भत्ता अथवा नियत वैयक्तिक वेतन के वेतनवृद्धि घटक को अधिवर्षिता लाभों के लिए गणना में लिया जाएगा।

(vi) जो अधिकारी उपर्युक्त खंड (ए) के अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि प्राप्त कर चुका है, वह वेतनमान के शीर्ष पर पहुँचने के एक वर्ष बाद इस उप-विनियम के खंड (बी), (सी), (डी), (ई), (एफ), (जी), (एच) एवं (आई) में उल्लिखित नियत वैयक्तिक भत्ता अथवा नियत वैयक्तिक वेतन प्राप्त कर सकेगा।”;

5. उक्त विनियमों के विनियम 21 में, -

(ए) उप-विनियम (6) में, खंड (बी) के स्पष्टीकरण में निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(बी) विनियम 5 के उप-विनियम (2) की व्याख्या में खंड (सी), (डी), (ई), (एफ), (जी), (एच) एवं (आई) के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यावसायिक योग्यता भत्ता अथवा व्यावसायिक योग्यता वेतन, महंगाई भत्ते के लिए गणना योग्य होगा।”

(बी) उप-विनियम (7) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम (8) जोड़ा जाएगा, अर्थात्—

“(8) 1 नवंबर, 2022 और उसके बाद से, —

(ए) महंगाई भत्ता, सूचकांक के प्रति प्रतिशत के अनुसार वेतनमान 1 प्रतिशत की दर से देय होगा।

(बी) उपर्युक्त तरीके से महंगाई भत्ते का भुगतान औद्योगिक कामगारों के लिए आधार 2016=100 हेतु अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के तिमाही औसत में 123.03 पॉइन्ट्स से अधिक की वृद्धि या गिरावट के प्रत्येक बदलाव के लिए किया जाएगा। 123.03 पॉइन्ट्स से अधिक के मामले में, 2016 के प्रत्येक दूसरे दशमलव स्थान में परिवर्तन के लिए वेतन पर महंगाई भत्ते में 0.01% का परिवर्तन होगा।

(सी) महंगाई भत्ते की दर में परिवर्तन तिमाही आधार पर 1 मई, 1 अगस्त, 1 नवंबर और 1 फरवरी को जारी किया जाएगा, जो निम्नलिखित पर आधारित है: -

महंगाई भत्ता जारी करने की तारीख	महीनों के सीपीआई पॉइन्ट्स का तिमाही औसत	महीने के लिए लागू
1 मई	जनवरी, फरवरी एवं मार्च	मई, जून एवं जुलाई
1 अगस्त	अप्रैल, मई एवं जून	अगस्त, सितंबर एवं अक्तूबर
1 नवंबर	जुलाई, अगस्त एवं सितंबर	नवंबर, दिसंबर एवं जनवरी
1 फरवरी	अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर	फरवरी, मार्च एवं अप्रैल

(डी) महंगाई भत्ते की कोई सीमा नहीं होगी।

(ई) त्रैमासिक औसत की गणना करते समय, केवल पहले दो दशमलव पर ही विचार किया जाएगा।” ;

6. उक्त विनियमों के विनियमन 22 में, उप-विनियमन (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(1) 1 नवंबर, 2022 को और उसके बाद से, -

(ए) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है वहां उससे वह जिस वेतनमान में है उस वेतनमान के प्रथम चरण के मूल वेतन के 0.35 प्रतिशत योग के बराबर या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा;

(बी) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की जाती है, वहां वह निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट दरों पर मकान किराया भत्ता के लिए पात्र होगा: -

तालिका

क्र. सं.	कार्यस्थल	मकान किराया भत्ता
(1)	(2)	(3)
1.	प्रमुख “ए” वर्ग के शहर तथा समूह ए के प्रोजेक्ट एरिया केन्द्र	वेतन का 10.0%
2.	एरिया I में अन्य स्थान तथा समूह बी के प्रोजेक्ट एरिया केंद्र तथा गोवा राज्य	वेतन का 9.0%
3.	अन्य स्थान	वेतन का 8.0%:

बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उसके प्रथम चरण के वेतन के 0.35 प्रतिशत से अधिक और उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया देय होगा जो उपर्युक्त तालिका के कॉलम (3) में दर्शायी गयी दरों के अनुरूप देय मकान किराया भत्ते का अधिकतम 150 प्रतिशत होगा।

नोट: अधिकारी के अपने स्वामित्व वाले आवास की लागत से जुड़े मकान किराया भत्ते के दावे भी अभी तक के समान मकान किराए भत्ते के 150 प्रतिशत तक सीमित होंगे।”

7. उक्त विनियमन के विनियम 23 में, -

(ए) उप-विनियम (1) एवं (2) के लिए, क्रमशः निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1) दिनांक 01 नवंबर, 2022 को और उसके बाद से यदि कोई अधिकारी निम्नलिखित तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित किसी स्थान पर सेवारत है तो वह उस स्थान के सामने कॉलम (2) में उल्लिखित दर पर शहर प्रतिपूरक भत्ता पाने के लिए पात्र होगा।

तालिका

क्र. सं.	स्थान	दर
(1)	(2)	(3)
1.	एरिया I एवं उससे ऊपर और गोवा राज्य में स्थित स्थान	₹ 2300/- प्रति माह
2.	पांच लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान तथा राज्यों की राजधानियां और चंडीगढ़, पुदुचेरी और पोर्ट ब्लेयर	₹ 1900/- प्रति माह

(2) दिनांक 01 नवंबर, 2022 और उसके बाद से विशेष क्षेत्र संबंधी भत्तों की दरें इन विनियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगी:

बशर्ते कि जहां सूची के कॉलम (1) में इंगित स्थानों में से किसी पर, उप-विनियम (10) के तहत प्रदान किए गए पहाड़ी क्षेत्र और ईंधन भत्ता भी देय है, तो अधिकारी निर्धारित दोनों भत्तों में से केवल उच्चतर भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा, दोनों के लिए नहीं:

बशर्ते कि दो भत्तों में से इस तरह के उच्चतर भत्ते 31 दिसंबर, 1989 को अधिकारी द्वारा आहरित विशेष भत्ते और पहाड़ी क्षेत्र और ईंधन भत्ते के कुल योग से कम हैं, तो इस तरह के अंतर को व्यक्तिगत भत्ते के रूप में तब तक संरक्षित किया जाएगा जब तक कि अधिकारी उस स्थान पर रहता है।”;

(बी) उप-विनियम (4), (5), (6) और (7) के लिए निम्नलिखित उप-विनियमन क्रमशः प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: —

“(4) दिनांक 1 अप्रैल, 2024 को और उसके बाद से यदि किसी अधिकारी को शैक्षणिक वर्ष के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है और यदि उसके एक या एक से अधिक बच्चे पूर्ववर्ती स्थान पर विद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं तो जिस तारीख को अधिकारी नई जगह पर रिपोर्ट करता है, उस तारीख से उसे शैक्षणिक वर्ष के अंत तक प्रत्येक बच्चे के लिए ₹2500/- प्रति माह मध्य शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ता दिया जाएगा:

बशर्ते कि यदि सभी बच्चे पूर्व स्थान पर पढ़ना बंद कर देते हैं, तो ऐसा भत्ता देय नहीं होगा।

(5) दिनांक 1 अप्रैल, 2024 को और उसके बाद से यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर किसी सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह प्रतिनियुक्ति के पद पर देय परिलब्धियों को प्राप्त करने के लिए अपना विकल्प दे सकता है अथवा वह अपने वेतन के अतिरिक्त वेतन के 7.75% की दर से अधिकतम ₹7500/- प्रति माह के अध्यधीन प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते ले सकता है जो उसे उसी स्थान पर बैंक की सेवा में पदस्थापित होने की स्थिति में मिलते हैं:

बशर्ते कि जहां ऐसे अधिकारी को किसी ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है जो उसी स्थान पर स्थित है या उस प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में जो बैंक के स्वामित्व में नहीं है, जहां वह अपनी प्रतिनियुक्ति से ठीक पहले तैनात था या प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में जो बैंक के स्वामित्व में नहीं है, तो उसे उसके वेतन के 4 प्रतिशत के बराबर अधिकतम ₹3750/- प्रति माह के अध्यधीन प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा:

बशर्ते कि, यदि किसी अधिकारी को मेट्रो या प्रमुख 'ए' श्रेणी के शहरों में, उसी नगरपालिका सीमा या शहरी इलाके के भीतर किसी दूसरे कार्यालय या शाखा में प्रतिनियुक्त किया जाता है, जहां ऐसी प्रतिनियुक्ति की दूरी मूल शाखा या कार्यालय से 20 किलोमीटर या उससे अधिक है, तो वह विनियमन 41 के उप-विनियमन (4) में उल्लिखित विराम भत्ते के लिए पात्र होगा;

(6) 1 अप्रैल, 2024 को और उसके बाद से यदि किसी अधिकारी को एक कैलेंडर माह के दौरान कम से कम चार दिनों की नियमित अवधि या कुल चार दिनों की नियमित अवधि के लिए उच्च स्तर पर किसी पद पर कार्य करने की आवश्यकता होती है, तो उसे उसके मूल वेतन के 15 प्रतिशत के बराबर उस अवधि के लिए अर्थात्प्राप्त स्थानापन्न भत्ता प्राप्त होगा। जिसके लिए वह कार्य करता है और स्थानापन्न भत्ता केवल भविष्य निधि और पेंशन के प्रयोजनों के लिए वेतन के रूप में माना जाएगा:

बशर्ते कि, जहां किसी अधिकारी को विनियम 6 के अंतर्गत केवल पदों के वर्गीकरण की समीक्षा के परिणामस्वरूप उच्चतर स्तर पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, वहां वह अधिकारी उस वर्गीकरण की समीक्षा के प्रभावी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए स्थानापन्न भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) 1 अप्रैल, 2024 को और इसके बाद से, प्रत्येक समापन के लिए एक अधिकारी ₹1500/- प्रति तिमाही की दर से समापन भत्ता देय के लिए पात्र होगा।” ;

(सी) उप-विनियमों (10), (11), (12) और (13) के लिए निम्नलिखित उप-विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(10) 1 नवंबर, 2022 को और इसके बाद से एक अधिकारी नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट पर्वतीय एवं ईंधन भत्ते के लिए पात्र होगा, अर्थात्: -

तालिका

क्र.सं.	स्थान	दर
(1)	(2)	(3)
1.	1000 मीटर और उससे अधिक परंतु 1500 मीटर से कम की ऊंचाई वाले स्थान और मार्कारा टाउन	वेतन का 2% अधिकतम ₹1450/- प्रति माह के अध्यधीन
2.	1500 मीटर और उससे अधिक परंतु 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 2.5% अधिकतम ₹1900/- प्रति माह के अध्यधीन
3.	3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 5% अधिकतम ₹3750/- प्रति माह;

(11) 01 नवंबर, 2022 को और उसके बाद से अधिकारी ₹850/- प्रति माह की दर से शिक्षण भत्ते और उस पर महंगाई भत्ते के लिए भी पात्र होंगे।

नोट: लागू महंगाई भत्ता सहित शिक्षण भत्ता, सेवानिवृत्ति लाभों, अर्थात् पेंशन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (नई पेंशन योजना) भविष्य निधि और ग्रेच्युटी सहित पेंशन के लिए गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

(12) दिनांक 01 नवंबर, 2022 को और इसके बाद से ऐसे अधिकारी जो शहरीय प्रतिपूर्ति भत्ते के लिए पात्र क्षेत्र से इतर अन्य क्षेत्र में पदस्थ हैं, वे ₹1200/- प्रतिमाह के निश्चित स्थान भत्ते के लिए पात्र होंगे। इस निश्चित भत्ते की गणना महंगाई भत्ते, अधिवर्षता लाभ, अर्थात् परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (नई पेंशन योजना), भविष्य निधि एवं ग्रेच्युटी सहित पेंशन के भुगतान के लिए नहीं की जाएगी।

(13) (ए) वित्तीय वर्ष 2023-24 से, सभी अधिकारी कर्मचारियों को बैंक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित चुनिंदा मापदंडों से उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार लगाए गए मेट्रिक्स के आधार पर परफॉर्मेंस लिंकड इंसेंटिव (पीएलआई) देय होगा:

- (i) चालू खाता और बचत खाता;
- (ii) अनर्जक आस्तियां;
- (iii) स्पेशल मेशन खाता;
- (iv) गैर-ब्याज आय;
- (v) कुल व्यवसाय;
- (vi) लाभप्रदता;
- (vii) आस्तियों पर प्रतिलाभ या इक्विटी पर प्रतिफल;
- (viii) सरकारी योजनाएं।

(बी) कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त खंड (ए) में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर 0-15 (अधिकतम) दिनों के वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) में किया जाएगा।”

8. कथित विनियम के विनियम 24 के अनुसार, -

(ए) उप-विनियमन (1) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

“(1) दिनांक 01 नवंबर 2022 को और इसके बाद से अधिकारी स्वयं और अपने परिजनों हेतु चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, जो अधिकारी के अपने प्रमाण पत्र के आधार पर इस तरह के व्यय को निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट अनुसार दावा की गई राशि के लिए खातों की विवरणी द्वारा समर्थित किया गया है, अर्थात्:-

तालिका

क्र.सं.	श्रेणी	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी और मध्य प्रबंधन श्रेणी	₹13000/- प्रतिवर्ष या व्यय की गई राशि जो भी कम हो
2.	वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी और उच्च कार्यपालक श्रेणी	₹15400/- प्रतिवर्ष या व्यय की गई राशि जो भी कम हो

नोट: (1) अप्रयुक्त चिकित्सा सहायता संचित करने की अनुमति अधिकारी को दी जा सकती है परंतु वह किसी भी समय ऊपर दी गई अधिकतम राशि के तीन गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए,

नोट 2: कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए, चिकित्सा सहायता योजना के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति को दो महीने, अर्थात् नवंबर, 2022 और दिसंबर, 2022 के लिए समानुपातिक रूप में बढ़ाई जाएगी”;

(बी) उप-विनियमन (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियमन डाला जाएगा, अर्थात्: -

“(4) सभी अधिकारी कर्मचारी आंखों की जांच के लिए प्रति वर्ष 500 रुपये की प्रतिपूर्ति के लिए भी पात्र होंगे।”।

9. कथित विनियम के विनियमन 25 में उप-विनियमन (2) के लिए निम्नलिखित उप-विनियमन प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(2) उप-विनियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, 01 नवंबर, 2022 को और इसके बाद से यदि बैंक चाहे तो अधिकारी को आवास उपलब्ध करा सकता है जिसके लिए अधिकारी द्वारा अपने वेतनमान के प्रथम स्तर के मूल वेतन के 0.35% के बराबर की राशि या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, का भुगतान किया जाएगा:

बशर्ते कि यदि ऐसे आवास पर अधिकारी को फर्नीचर भी उपलब्ध कराया गया हो तो उनके वेतनमान के प्रथम स्तर के मूल वेतन के 0.075% के बराबर अतिरिक्त राशि उनसे वसूल की जाएगी:

बशर्ते यह भी कि यदि बैंक द्वारा ऐसी आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है तो बिजली, पानी, गैस और सफाई संबंधी प्रभार अधिकारी द्वारा वहन किए जाएंगे।”।

10. कथित विनियम के विनियम 31 में, निम्नलिखित परंतुक शामिल किया जाएगा, अर्थात्: -

“बशर्ते कि जहां मंजूरी देने वाला प्राधिकारी अधिकारी की अवकाश को अस्वीकार करता है या स्थगित करता है, वह इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।”।

11. उक्त विनियमों के विनियम 32 में, उप-विनियमन (2) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियमन शामिल किए जाएंगे, अर्थात्: -

“(3) 01 अप्रैल, 2024 को और इसके बाद से, एक अधिकारी कर्मचारी एक वर्ष में चार बार आधे दिन के लिए दो दिन का आकस्मिक अवकाश प्राप्त करने का पात्र होगा, जिसमें से दो अवसर सुबह और दो अवसर दोपहर में होंगे: बशर्ते कि इस श्रेणी के तहत आकस्मिक अवकाश चौबीस घंटे पहले आवेदन करने के बाद प्राप्त किया जाएगा:

बशर्ते कि आकस्मिक अवकाश में उपलब्ध शेष अवकाश को अप्राप्य आकस्मिक अवकाश खाते में परिवर्तित करते समय, उपलब्ध शेष अवकाश में कोई फ्रेक्शन हो, तो उसे अनदेखा कर दिया जाएगा।”।

12. उक्त विनियमों के विनियमन 33 में, -

(ए) उप-विनियमों (4) और (5) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम क्रमशः प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

“(4) 1 जून, 2015 को और उसके बाद से, विशेषाधिकार अवकाश दो सौ सत्तर दिनों से अधिक संचित नहीं की जा सकती है, सिवाय इसके कि जहां अवकाश का आवेदन किया गया हो और उसे अस्वीकार कर दिया गया हो:

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 को और उसके बाद से विशेषाधिकार अवकाश का भुनाया जाना अधिकतम दो सौ पचपन दिनों तक सीमित रहेगा:

बशर्ते यह भी कि एक अधिकारी अपनी पसंद के किसी भी त्योहार के समय प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए पांच दिनों की दर से विशेषाधिकार अवकाश को भुनाने के लिए भी पात्र होगा और जो अधिकारी पचपन वर्ष और उससे अधिक आयु पूरी कर चुके हैं, वह अपनी सेवानिवृत्ति तक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए सात दिनों की दर से विशेषाधिकार अवकाश को भुनाने के लिए पात्र होगा।

(5) विशेषाधिकार अवकाश लेने के इच्छुक अधिकारी को अवकाश किराया रियायत के प्रयोजन को छोड़कर, ऐसी अवकाश का लाभ उठाने के अपने इरादे के बारे में कम से कम दस दिन पहले सूचना देनी होगी।

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 को और उसके बाद से पंजीकृत ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकारी समिति के सदस्यों के लिए विशेषाधिकार अवकाश का लाभ उठाने के लिए दस दिनों की ऐसी अग्रिम सूचना की आवश्यकता नहीं होगी।”;

(बी) उप-विनियम (6) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

“(7) 1 अप्रैल, 2024 को और उसके बाद से विशेषाधिकार अवकाश की गणना के प्रयोजनों के लिए, आकस्मिक अवकाश और अनिवार्य अवकाश को छोड़कर प्राप्त सभी प्रकार की अवकाश को शामिल नहीं किया जाएगा”।

13. उक्त विनियमों के विनियम 34 में, -

(ए) उप-विनियमन (1) में, निम्नलिखित प्रावधान जोड़ें जाएंगे, अर्थात्: -

“बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 को और उसके बाद से एक अधिकारी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक महीने की दर से बीमारी की अवकाश के लिए पात्र होगा:

परन्तु यह भी कि बीमारी अवकाश की कुल संख्या (विनियम 35 में उल्लिखित अतिरिक्त बीमारी अवकाश सहित) अधिकारी की संपूर्ण सेवा में सात सौ बीस दिनों से अधिक नहीं होगी।”;

(बी) उप-विनियम (5) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्: -

“(6) 1 अप्रैल, 2024 को और उसके बाद से एकल पुरुष अभिभावक अपने आठ साल और उससे कम उम्र के बच्चों की बीमारी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन चिकित्सा अवकाश का लाभ उठा सकता है।

(7) 1 अप्रैल, 2024 को और उसके बाद से महिला कर्मचारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना प्रति माह एक दिन का चिकित्सा अवकाश ले सकती हैं।

(8) 1 अप्रैल, 2024 को और उसके बाद से, अधिकारी कर्मचारी पंद्रह वर्ष और उससे कम आयु के अपने स्पेशल चाइल्ड की बीमारी के लिए एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम दस दिनों की अवधि के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन चिकित्सा अवकाश ले सकते हैं।

(9) 1 अप्रैल, 2024 को और उसके बाद से, 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के अधिकारी कर्मचारी, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम तीस दिनों की अवधि के लिए कार्य स्थल के अलावा किसी अन्य केंद्र में अपने पति या पत्नी के अस्पताल में भर्ती होने पर चिकित्सा अवकाश ले सकते हैं।”।

14. उक्त विनियमों के विनियम 36 में, उप-विनियम (1) में, -

(ए) खंड (ए) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(ए) एक महिला अधिकारी किसी भी एक अवसर पर छह महीने से अधिक नहीं और उसकी सेवा की पूरी अवधि के दौरान बारह महीने की अवधि के लिए मूल वेतन पर मातृत्व अवकाश के लिए पात्र होगी:

बशर्ते कि जुड़वा बच्चों के प्रसव के मामले में, मातृत्व अवकाश की अवधि आठ महीने होगी:

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 को और उसके बाद से एक प्रसव में दो से अधिक बच्चों के प्रसव के मामले में, मातृत्व अवकाश की अवधि बारह महीने होगी:

बशर्ते कि मातृत्व अवकाश को, आकस्मिक अवकाश को छोड़कर, किसी अन्य प्रकार की अवकाश के साथ जोड़कर लिया जा सकता है।”;

(बी) खंड (डी) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(डी) एक महिला अधिकारी एक वर्ष से कम आयु के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए सेवा के दौरान एक बार अधिकतम नौ महीने की अवधि के लिए अवकाश ले सकती है, जो निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन है, अर्थात्: -

(ए) केवल एक बच्चे को गोद लेने के लिए अवकाश दी जाएगी;

(बी) बच्चे को गोद लेना एक उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए और कर्मचारी को इस तरह की अवकाश को मंजूरी देने के लिए बैंक को दत्तक ग्रहण विलेख प्रस्तुत करना चाहिए;

(सी) यह अवकाश उन मामलों में जैविक मां के लिए भी उपलब्ध होगी जहां बच्चे का जन्म सरोगेसी के माध्यम से हुआ है।

(डी) सेवा की पूरी अवधि के दौरान बारह महीने की समग्र पात्रता के भीतर अवकाश का लाभ उठाया जाएगा”

(सी) खंड (ई) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(एफ) 1 अप्रैल, 2024 को और उसके बाद से इन विट्रो फर्टिलिटी (आईवीएफ) उपचार के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन बारह महीने की समग्र सीमा के भीतर मातृत्व अवकाश भी लिया जा सकता है।

(जी) 1 अप्रैल, 2024 को और उसके बाद से महिला कर्मचारी द्वारा मृत शिशु को जन्म देने अथवा जन्म के अट्टाईस दिनों के भीतर शिशु की मृत्यु के मामले में साठ दिनों तक विशेष मातृत्व अवकाश ली जा सकती है।”।

15. उक्त विनियम के विनियम 37ए के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जा सकता है, अर्थात्: -

“37ए. विशेष आकस्मिक अवकाश और विशेष अवकाश - (1) 1 नवंबर, 2020 से, एक अधिकारी कर्मचारी उन अवसरों पर विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र होगा जब वह शाखा जहां अधिकारी कार्यरत है या जिस स्थान पर वह रह रहा है, कर्फ्यू, दंगों, निषेधात्मक आदेशों, प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ और इसी प्रकार की परिस्थितियों से प्रभावित है।

(2) 1 नवंबर, 2020 से शारीरिक या अस्थि विकलांग अधिकारी चार दिनों की विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र होगा।

(3) 1 अप्रैल, 2024 से, अखिल भारतीय अधिकारी संघों या संघों के प्रमुख पदाधिकारियों को एक कैलेंडर वर्ष में पच्चीस दिनों तक विशेष अवकाश प्रदान की जाएगी।

(4) 1 अप्रैल, 2024 से, जो अधिकारी विभागीय जांच में बचाव प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनियुक्त हैं, के द्वारा अधिकारी कर्मचारी के बचाव पक्ष की तैयारी करने के उद्देश्य से एक दिन की विशेष अवकाश ली जा सकती है।

बशर्ते कि इस तरह की विशेष अवकाश एक वर्ष में अधिकतम दस अवसरों पर ली जाएगी।

(5) किसी अधिकारी को विशेष आकस्मिक अवकाश और कोई स्पेशल अवकाश भी दी जा सकेगी जैसा कि सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा विनिर्धारित किया जाएगा।”

16. उक्त विनियमों के विनियम 37ए के बाद, निम्नलिखित विनियम को शामिल किया जाएगा, अर्थात्: -

“37बी. शोक अवकाश.- एक अधिकारी कर्मचारी को परिवार के सदस्यों (पति/पत्नी, बच्चों, माता-पिता और सास-ससुर) के निधन पर बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय किए जाने वाले दिनों की संख्या के लिए शोक अवकाश प्रदान की जाएगी:

बशर्ते कि मध्यावधि अवकाश शोक अवकाश का हिस्सा होंगी:

बशर्ते कि उक्त अवकाश को मृत्यु के पंद्रह दिनों की अधिकतम अवधि के भीतर लिया जाना चाहिए:

बशर्ते कि उक्त अवकाश को विशेषाधिकार अवकाश की गणना के उद्देश्य से “सक्रिय सेवा” के रूप में नहीं माना जाएगा।”

17. उक्त विनियमों के विनियमन 41 में, -

(ए) उप-विनियमन (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(1) 1 अप्रैल, 2024 को और उसके बाद जहां भी किसी अधिकारी को झूटी पर यात्रा करने की आवश्यकता होगी, निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे, अर्थात्: -

(ए) कनिष्ठ प्रबंधन वेतनमान में एक अधिकारी राजधानी या शताब्दी या तेजस या वंदे भारत या अमृत भारत आदि जैसी प्रीमियम ट्रेनों सहित किसी भी ट्रेन से प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित कोच में यात्रा करने के लिए पात्र होगा (लक्जरी ट्रेनों को छोड़कर):

बशर्ते कि ऐसा अधिकारी व्यवसाय या सार्वजनिक हित की अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से हवाई (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा कर सकता है।

(बी) मध्यम प्रबंधन वेतनमान में एक अधिकारी खंड (ए) में उल्लिखित प्रीमियम ट्रेनों सहित किसी भी ट्रेन द्वारा एसी 1 श्रेणी में यात्रा करने के लिए पात्र होगा:

बशर्ते कि ऐसा अधिकारी हवाई (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा कर सकता है यदि निर्धारित यात्रा की दूरी पांच सौ किलोमीटर से अधिक है:

बशर्ते कि ऐसा अधिकारी कम दूरी के लिए भी हवाई (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा कर सकेगा, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवसाय या सार्वजनिक हित की अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी को अनुमति दी गई हो;

सी) वरिष्ठ प्रबंधन या उच्च कार्यपालक श्रेणी के अधिकारी किसी भी ट्रेन द्वारा प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित कोच जिसमें प्रीमियम ट्रेनों भी शामिल हैं जैसा कि खंड (ए) में उल्लिखित है या हवाई (इकोनॉमी क्लास) यात्रा करने के लिए पात्र है;

डी) वरिष्ठ प्रबंधन या उच्च कार्यपालक श्रेणी के अधिकारी उन स्थानों के बीच कार से यात्रा कर सकते हैं जो हवाई या रेलमार्ग से जुड़े नहीं हैं, बशर्ते कि दूरी पांच सौ किलोमीटर से अधिक न हो;

बशर्ते कि जबकि दो स्थानों के बीच की दूरी का एक बड़ा हिस्सा हवाई या रेलमार्ग द्वारा तय किया जा सकता है, तो केवल शेष दूरी को सामान्य रूप से कार द्वारा कवर किया जाना चाहिए;

(ई) किसी अन्य अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवसाय की अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए, अपने वाहन से या टैक्सी या बैंक के वाहन से यात्रा करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है;

एफ) किसी भी संवर्ग या वेतनमान का अधिकारी सड़क या हवाई या रेल से जुड़े नहीं होने वाले स्थानों के बीच जल परिवहन द्वारा डीलक्स केबिन श्रेणी में यात्रा करने के लिए पात्र होगा।;

(जी) एक अधिकारी प्रीमियम ट्रेनों (लक्जरी ट्रेनों को छोड़कर) द्वारा यात्रा के किराए के लिए पात्र होगा।

नोट 1: ट्रेन किराए पर लगाए गए माल और सेवा कर शुल्क निर्धारित पात्रता के अतिरिक्त एवं अधिक होंगे।

नोट 2: प्रचलित गतिशील किराया प्रणाली को ध्यान में रखते हुए, बुकिंग की तारीख पर लिए गए ट्रेन टिकटों की लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(बी) उप-विनियम (4) में, खंड (ए) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(ए) हॉल्टिंग भत्ते- 1 अप्रैल, 2024 को और उसके बाद तालिका के कॉलम (2) में निर्धारित श्रेणी या वेतनमान का अधिकारी उसके कॉलम (3) में निर्धारित संगत दरों पर प्रति दिन हॉल्टिंग भत्ता का हकदार होगा, अर्थात्: -

तालिका

क्रम संख्या	अधिकारियों की श्रेणी या वेतनमान	हॉल्टिंग भत्ता			
		मेट्रो रु.	प्रमुख 'ए' श्रेणी के शहर रु.	क्षेत्र-1 रु.	अन्य स्थान रु.
(1)	(2)	(3)			
1.	वेतनमान-VI और उससे ऊपर के अधिकारी	4050	2925	2475	2150
2.	वेतनमान-IV और V के अधिकारी	3375	2925	2475	2150
3.	वेतनमान-I, II और III के अधिकारी	2925	2475	2150	1800;

बशर्ते कि जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटे से कम लेकिन चार घंटे से अधिक है, वहां उपरोक्त निर्धारित दरों की आधी राशि पर हॉल्टिंग भत्ता देय होगा।

स्पष्टीकरण- हॉल्टिंग भत्ते की गणना के प्रयोजन के लिए, प्रतिदिन चौबीस घंटे की प्रत्येक अवधि या उसके बाद के किसी भी हिस्से का अर्थ होगा, जिसे हवाई यात्रा की स्थिति में प्रस्थान के लिए रिपोर्टिंग समय और अन्य मामलों में प्रस्थान के निर्धारित समय से लेकर आगमन के वास्तविक समय तक गिना जाएगा और जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि चौबीस घंटे से कम है, प्रतिदिन का अभिप्राय कम से कम आठ घंटे की अवधि होगी।

18. उक्त विनियमों के विनियम 42 में,-

(ए) उप-विनियमन (3) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(3) 1 अप्रैल, 2024 को और उसके पश्चात अधिकारी के स्थानांतरण पर अधिकारी पैकिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा आदि से जुड़े खर्चों के लिए एकमुश्त राशि प्राप्त करने का पात्र होगा, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट है, अर्थात्: -

तालिका

क्रम संख्या	श्रेणी या वेतनमान	राशि
(1)	(2)	(3)
1.	वरिष्ठ प्रबंधन और उच्च कार्यपालक (वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारी)	Rs.50000/-
2.	कनिष्ठ प्रबंधन और मध्यम प्रबंधन (वेतनमान III तक के अधिकारी)	Rs.40000/-

(बी) उप-विनियमन (4) में, परंतुक के लिए, निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2024 को और उसके बाद, जहां बैंक द्वारा पदस्थापना के नए स्थान पर अधिकारी को कोई आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है और जहां अधिकारी को अपने नियंत्रण से परे कारणों से कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया में निर्धारित राशि से अतिरिक्त राशि खर्च कर सकता है, सक्षम प्राधिकारी, नए स्थान पर ऐसे अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से, योग्यता के आधार पर पंद्रह दिनों की अवधि के लिए या उसे आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने तक, जो भी पहले हो, या तो आवास और बोर्डिंग शुल्क या हॉल्टिंग भत्ता देने पर विचार कर सकता है।"

19. उक्त विनियमों के विनियमन 44 के लिए, निम्नलिखित विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"44. अवकाश यात्रा रियायत- (1) चार वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक के दौरान, एक अधिकारी दो वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक में एक बार अपने मूल निवास स्थान की यात्रा के लिए अवकाश यात्रा रियायत के लिए पात्र होगा:

बशर्ते कि वह दो साल के एक ब्लॉक में अपने मूल निवास के स्थान तक और दो साल के दूसरे ब्लॉक में भारत के किसी भी स्थान पर सबसे छोटे मार्ग से यात्रा कर सके।

(2) 1 अप्रैल, 2024 से, वैकल्पिक रूप से, एक अधिकारी चार साल के ब्लॉक या दो साल के ब्लॉक के दौरान किसी भी समय एक विकल्प का प्रयोग करके, जैसा भी मामला हो, अपनी अवकाश यात्रा रियायत (मूल निवास की यात्रा के अलावा) को सरेंडर और भुनाता है, जिस पर वह ट्रेन से यात्रा की श्रेणी के लिए पात्र किराए के बराबर राशि प्राप्त करने का हकदार होगा, जिसके लिए वह एक दूरी तक की यात्रा करने का हकदार है कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी / वेतनमान-I, मध्यम प्रबंधन श्रेणी/वेतनमान-II और मध्यम प्रबंधन श्रेणी/वेतनमान-III में अधिकारियों के लिए 5,500

किलोमीटर (वन-वे) और वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी/वेतनमान-IV और उससे उच्च स्तर के अधिकारियों के लिए यात्रा की निर्धारित दूरी 6,500 किलोमीटर (वन-वे) की है:

बशर्ते कि एक अधिकारी जो अपनी अवकाश यात्रा रियायत को भुनाने का विकल्प चुनता है, वह उस ब्लॉक के दौरान केवल एक बार अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए दावे को प्राथमिकता देगा, जिसमें इस तरह के नकदीकरण का लाभ उठाया गया है और अवकाश यात्रा रियायत का लाभ उठाते समय विशेषाधिकार अवकाश के नकदीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है।

(3) जिस माध्यम और श्रेणी से कोई अधिकारी अवकाश यात्रा रियायत का लाभ उठा सकता है, वह वही होगा जो अधिकारी सामान्य रूप से स्थानांतरण पर यात्रा करने का हकदार है और अन्य नियम और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए किसी अधिकारी द्वारा अवकाश यात्रा रियायत का लाभ उठाया जा सकता है, जिसे समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा:

बशर्ते यह कि दिनांक 1 अप्रैल, 2024 से, कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I में कोई अधिकारी अवकाश यात्रा रियायत का लाभ उठाता है, तो वह इकोनॉमी क्लास में सबसे कम किराए वाली हवाई यात्रा करने का पात्र होगा, जिसके लिए वास्तविक किराए या यात्रा की गई दूरी के लिए ट्रेन द्वारा एसी प्रथम श्रेणी के लिए लागू किराया, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाएगी और उक्त नियम मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II और मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III के किसी अधिकारी द्वारा अवकाश यात्रा रियायत का लाभ उठाते समय, जहां दूरी पांच सौ किलोमीटर से कम है, के लिए भी लागू होंगे।

(4) प्रत्येक चार वर्ष में एक बार, जब कोई अधिकारी अवकाश यात्रा रियायत का लाभ उठाता है, तो उसे एक बार में तीस दिनों तक के अपने विशेषाधिकार अवकाश को समर्पित करने और उसके नकदीकरण की अनुमति दी जाएगी या उसे दो वर्षों के एक ब्लॉक में अपने गृह नगर की यात्रा और दूसरे ब्लॉक में भारत में किसी भी स्थान पर यात्रा करते समय, प्रत्येक ब्लॉक में अधिकतम पंद्रह दिनों या एक ब्लॉक में तीस दिनों की विशेषाधिकार अवकाश के नकदीकरण की अनुमति दी जा सकती है और अवकाश नकदीकरण के प्रयोजन के लिए उस महीने के लिए देय सभी वेतन स्वीकार्य होंगे जिसके दौरान अवकाश यात्रा रियायत का लाभ उठाया जाता है:

अधिकारी को, अपनी इच्छा के अनुसार, प्रधानमंत्री राहत कोष में दान के लिए एक दिन के अतिरिक्त विशेषाधिकार अवकाश का नकदीकरण करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि वह बैंक को इस आशय का एक पत्र और राहत कोष में राशि जमा करने के लिए प्राधिकृत करे।

(5) बैंक की सेवा में एक साथ कार्य करने वाले पति और पत्नी द्वारा अवकाश यात्रा रियायत का लाभ अलग-अलग रूप से उठाया जा सकता है।

(6) पूर्वोत्तर राज्यों में काम करने वाले स्टाफ सदस्यों के लिए, अवकाश यात्रा रियायत गुवाहाटी से आरंभ होगी और उनके कार्यस्थल से गुवाहाटी के लिए पात्र ट्रेन किराए का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

(7) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से चेन्नई या कोलकाता के लिए, लक्षद्वीप से कोच्चि के लिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर में दूर-दराज की शाखाओं या किसी अन्य क्षेत्र, जो सीधे ट्रेन से जुड़े नहीं हैं, के लिए पात्र किराए की इन क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन तक की सामान्य पात्रता के साथ अवकाश यात्रा रियायत के तहत अतिरिक्त प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(8) निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले अधिकारी के साथ यात्रा पर जाने वाले एस्कॉर्ट के लिए अवकाश यात्रा रियायत सुविधा की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाएगी, अर्थात्: -

- (ए) प्रत्येक अवसर पर सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाएगी;
- (बी) अधिकारी की शारीरिक दिव्यांगता की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि यात्रा के लिए एक एस्कॉर्ट की आवश्यकता हो और संदेह की स्थिति में, विभाग के प्रमुख या नियंत्रक का निर्णय अंतिम होगा;
- (सी) इस तरह की निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले अधिकारी के साथ यात्रा के लिए उसके परिवार का कोई वयस्क सदस्य नहीं है जो उस पर निर्भर हो;
- (डी) ऐसी निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले अधिकारी और एस्कॉर्ट रेल या बस किराए में, तो रेलवे या राज्य सड़क प्राधिकरणों द्वारा ऐसे मामलों में दी जाने वाली किसी रियायत यदि कोई हो का लाभ उठाएंगे; तथा
- (ई) कोई अन्य व्यक्ति जो आश्रित के रूप में अवकाश यात्रा रियायत का हकदार है लेकिन वह इस तरह के निर्दिष्ट दिव्यांगता अधिकारी के साथ यात्रा पर नहीं जाता है।
- (9) जहां किसी अधिकारी ने अवकाश यात्रा रियायत या अग्रिम रूप से अवकाश के लिए आवेदन किया है और टिकट भी बुक किए हैं और प्रबंधन द्वारा अवकाश यात्रा रियायत को अस्वीकार या स्थगित कर दिया गया है, तब निरस्तीकरण प्रभारों की प्रतिपूर्ति बैंक द्वारा की जाएगी।
- (10) जहां किसी अधिकारी ने निर्धारित समय के अनुसार अवकाश यात्रा रियायत या अवकाश के लिए आवेदन किया है और उसे मंजूरी दी गई है और जब ट्रेन टिकटों की अग्रिम बुकिंग संभव नहीं है, तब तत्काल या प्रीमियम तत्काल के तहत खरीदे गए टिकटों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।”।

20. उक्त विनियमों की अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“अनुसूची

[विनियमन 23 का उप-विनियमन (2) देखें]

दिनांक 1 नवंबर, 2022 को और उसके बाद से, कोई अधिकारी विशेष क्षेत्र भत्ते के लिए तब तक पात्र होगा जब तक कि उन्हें पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वापस नहीं लिया जाता या संशोधित नहीं किया जाता है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट है, अर्थात्:-

तालिका

विशेष क्षेत्र भत्ता

क्रम संख्या	स्थान	भत्ते (रुपये में)	
		₹48,481/- से कम भुगतान करें	₹48,481/- से अधिक का भुगतान करें
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मिजोरम		
	(ए) चिम्पतुईपुई जिला और लुंगलेई जिले के लुंगलेई शहर से 25 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र।	4100	5300

	(बी) लुंगलेई शहर से 25 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्रों को छोड़कर पूरा लुंगलेई जिला	4100	5300
	(सी) पूरा आइजोल जिला	2700	3400
2	नागालैंड	4100	5300
3	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		
	(ए) उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, छोटा अंडमान, निकोबार और नारकोंडम द्वीप समूह	4100	5300
	(बी) दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	4100	5300
4	सिक्किम	4100	5300
5	लक्षद्वीप द्वीप समूह	4100	5300
6	असम	1000	1200
7	मेघालय	1000	1200
8	त्रिपुरा		
	(ए) त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्र	4100	5300
	(बी) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर पूरे त्रिपुरा में	2700	3400
9	मणिपुर	2700	3400
10	अरुणाचल प्रदेश		
	(ए) अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र	4100	5300
	(बी) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर पूरे अरुणाचल प्रदेश में	4100	5300
11	ए.- जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश		
	(1) कठुआ जिला: नियाबत बानी, लोही, मल्हार और मल्लोड़ी	4100	5300
	(2) उधमपुर जिला:		
	(ए) दूदू वसंतगढ़, लंदेर भामाग इलाका, ठाकराकोट और नागेट	4100	5300
	(बी) (ग) में शामिल क्षेत्रों के अतिरिक्त माहोर तहसील के सभी क्षेत्र	4100	5300
	(सी) तहसील मोहरे में कंबन साइड से गोयल तक के क्षेत्र और केसी की ओर से अर्नास तक के क्षेत्र	4100	5300
	(3) डोडा जिला: कश्मीर तहसील में पद्म के इलाके और नियाबत नौगाम	4100	5300
	(4) बारामूला जिला:		
	(ए) पूरा गुरेज-निराबत, तंगदर उप-मंडल और केरन इलाका	4100	5300
	(बी) मैटचिल	4100	5300

	(5) पुंछ तथा राजौरी जिला: पुंछ और राजौरी नगरों को छोड़कर पुंछ और राजौरी जिले के अन्य क्षेत्र और सुंदरबनी क्षेत्र तथा दोनों जिलों के अन्य शहरी क्षेत्र	2700	3400
	(6) उपरोक्त (1) से (5) के अलावा, अन्य क्षेत्र जो वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलओसी) से 8 किमी से कम दूरी पर है या वह क्षेत्र जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा उनके स्टाफ के लिए बॉर्डर भत्ते के रूप में पात्रता हेतु घोषित किया जाता है।	2700	3400
	बी.- केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख: लेह जिला: नोयामा और नोब्रे ज़ांस्कर जिले के अन्य सभी स्थान	4100	5300
12	हिमाचल प्रदेश		
	(1) चंबा जिला		
	(ए) पांगी तहसील, भरमौर तहसील में निम्नलिखित पंचायतें और गांव: पंचायतें: बड़गांव, बाजोल, देओल कुगटी, नयागम और टुंडा गांव: ग्राम पंचायत जगत का घाटू, ग्राम पंचायत चौहटा का कनारसी	4100	5300
	(बी) (ए) में शामिल पंचायतों और गांवों को छोड़कर भरमौर तहसील,	4100	5300
	(सी) भारतीयात तहसील में झंडरू पंचायत, चुराह तहसील, डलहौजी टाउन (मूल बनीखेत सहित)	2700	3400
	(2) किन्नौर जिला		
	(ए) असरंग, चितकुल और हंगोकुनो/चारंग पंचायत, छोटा खंभा, नथपा और रूपी की ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करते हुए 15/20 क्षेत्र, पूह उपखंड, उपरोक्त निर्धारित पंचायत क्षेत्र को छोड़कर	4100	5300
	(बी) उपरोक्त (ए) में शामिल क्षेत्रों को छोड़कर समग्र जिला	4100	5300
	(3) कुल्लू जिला		

	(ए) खरगा, कुशवर और सर्गा की ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करते हुए निर्मन्द तहसील के 15/20 क्षेत्र	4100	5300
	(बी) बाहरी-सराज (निर्मद तहसील के जकात खाना और बरौं गांवों को छोड़कर) और संपूर्ण जिला (बाहरी सराज क्षेत्र और पंडरबीस के परगना को छोड़कर परंतु निर्मद तहसील के जगत खाना और बरौं को सम्मिलित करते हुए)	2700	3400
	(4) लाहौल और स्पीति जिला: लाहौल और स्पीति का संपूर्ण क्षेत्र:	4100	5300
	(5) शिमला जिला		
	(ए) कूट, लवाना सादना, सरपरा और चंडी बरान्दा की पंचायतों को सम्मिलित करते हुए रामपुर तहसील के 15/20 क्षेत्र	4100	5300
	(बी) दोदरा-कवर तहसील, रामपुर में दारकली की ग्राम पंचायत, काशपथ तहसील और मुनीश, परगना सराहन की घोरी चैबीस	4100	5300
	(सी) चौपाल तहसील (i) परगना सराहन के घोरिस, पंजगांव, पत्सनी, नौबिस और तीन कोटी, (ii) तकलेश क्षेत्र की देओठी ग्राम पंचायत, (iii) परगना बारावीस, (iv) रामपुर तहसील के कस्बा रामपुर और परगना रामपुर के घोरी नोग, (डी) शिमला टाउन और उसके नगर परिसर (ढाली, जातोग, कासुम्सि, माशोबरा, तारादेवी तथा तूतू)	2700	3400
	(6) कांगड़ा जिला:		
	(ए) बड़ा भांगल और छोटा भांगल के क्षेत्र	4100	5300
	(I) कांगड़ा जिले का धर्मशाला टाउन और नगरपालिका सीमा के बाहर परंतु धर्मशाला टाउन में सम्मिलित स्थित निम्नलिखित कार्यालय: (ए) वुमेंस आईटीआई, दारी, (बी) मैकेनिकल वर्कशॉप, रामनगर, (सी) बाल-कल्याण और टाउन और कंट्री प्लानिंग कार्यालय, सकोह (डी) लोवर सकोह का सीआरएसएफ कार्यालय,	2700	3400

	(ई) कांगड़ा मिल्क सप्लाय योजना, डुगैर (एफ) एचआरटीसी वर्कशॉप, साधेर (जी) जोनल मलेरिया कार्यालय, दारी, (एच) फॉरस्ट कॉर्पोरेशन कार्यालय, शामनगर, (आई) टी फैक्टरी, दारी, (जे) आईपीएच उपविभाग, दारी (के) सेटलमेंट कार्यालय, शामनगर, (एल) बिनवा प्रोजेक्ट, शामनगर (II) पालमपुर में एचपीकेवीवी परिसर सहित पालमपुर टाउन और इसकी नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय जो पालमपुर टाउन में शामिल हैं: (ए) एच.पी कृषि विश्वविद्यालय परिसर, (बी) कैटल डेवेलपमेंट कार्यालय/जर्सी फॉर्म, बनौरी, (सी) सेरिकल्चर कार्यालय/इंडो जर्मन एग्रीकल्चर वर्कशॉप / एचपीपीडबल्यूडी डिविजन, बुंदला (डी) इलेक्ट्रिकल सब डिविजन, लोहना, (ई) डीपीओओ कॉर्पोरेशन, बुंदला, (एफ) इलेक्ट्रिकल एचपीएसई डिविजन, घुग्गर		
	(7) मंडी जिला:		
	जोगिंदरनगर तहसील की छुहर वैली, थुनाग तहसील की पंचायतें: बागरा, चातरी, छोटधर, गारगुसाहीन, गट्टू, गारयस, जंझेली, जरयार, जोहर कलहानी, कलवान, खोलानाल, लोथ, सिल्लीबागी सोमाचन, थाचधर, ताची, थाना धरमपुर ब्लॉक की निम्नलिखित पंचायतें: बिंगा, कामलाह, सकलाना, तनयार और ताराखोलह, करसोग तहसील की पंचायतें- बलीधर, बागरा, गोपालपुर, खाजोल, महोग, मेहूदी, मंज, पेखी,	2700	3400

	सैंज, सराहन और तेवान, सुंदरनगर तहसील की पंचायतें - बोही, बटवारा, धन्यारा, पौरा-कोठी, सेरी और शोजा		
	(8) सिरमौर जिला: (ए) निम्नलिखित पंचायतें (i) बानी, बाखाली (पाछड़ तहसील); (ii) भारोग भेनेरी (पाओंता तहसील); (iii) बिरला (नाहन तहसील); (iv) डिब्बर (पाछड़ तहसील); और (v) थाना कासोगा (नाहन तहसील) (b) थांसगिरी ट्रैक्ट	2700	3400
	(9) सोलन जिला: मंगल पंचायत	2700	3400
	(10) उक्त 1 से 9 मद में सम्मिलित न किए गए हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्र	1000	1200
13	उत्तराखण्ड: चमोली, पिथौरागढ़, उत्तर काशी, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिलों के तहत क्षेत्र	4100	5300
14	पश्चिम बंगाल: दक्षिण 24 परगना जिला सुंदरबन क्षेत्र (डैम्पियर हॉज की लाइन के दक्षिण), अर्थात् भगातुश खली (रामपुरा), कुमीरमारी (बगना), झिंगा खली, सजनाखली, गोसाबा, अमलामथी (बिद्या), कैनिंग, कुलतली, पियाली, नलगराहा, रैदिघी, भांची, पाथर प्रतिमा, भागवतपुर, सप्तमुखी, नामखाना, सीकरपुर, काकद्वीप, सागर, मौसिनी, कालीनगर, हरोआ, हिंगलगंज, बसंती, क्यूमारी, कुलटोला, घुशीघाटा (कुल्टी)	1000	1200

शैलेंद्र सिंह, मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.प्र. एवं विपणन)

[विज्ञापन-III/4/असा./222/2026-27]

नोट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और बाद में भारत के राजपत्र में प्रकाशित निम्नलिखित अधिसूचनाओं के माध्यम से संशोधित किए गए थे, अर्थात्: -

क्रम संख्या	राजपत्र अधिसूचना संख्या	सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि
1.	एचओ:एसटीएफ:ए:10/13:455 दिनांक 07-03-1988	26-03-1988
2.	एचओ:एसटीएफ:ए:10/13:456 दिनांक 07-03-1988	26-03-1988

3.	एचओ:एसटीएफ:ए:10/15:73 दिनांक 21-01-1989	25-02-1989
4.	एचओ:एसटीएफ:ए:10/15:267 दिनांक 01-03-1989	01-04-1989
5.	एचओ:एसटीएफ:ए:10/10:792 दिनांक 10-05-1990	16-06-1990
6.	एचओ:ओएसआर & आईआर:ए/10/14:1030 दिनांक 21-07-1993	25-09-1993
7.	एचओ:ओएसआर & आईआर:ए/10/16:1029 दिनांक 21-07-1993	25-09-1993
8.	एचओ:ओएसआर & आईआर:ए/10/9:657 दिनांक 05-06-1993	24-07-1993
9.	एचओ:ओएसआर & आईआर:ए/10/14:704 दिनांक 30-04-1994	16-07-1994
10.	एचओ:ओएसआर & आईआर:ए/6/9:2828 दिनांक 17.01.1997	22-02-1997
11.	एचओ:ओएसआर & आईआर:ए/12/9:2902 दिनांक 11-12-1999	24-01-2000
12.	एचओ:ओएसआर & आईआर:ए/10/18:1057 दिनांक 15.05.2000	29-07-2000
13.	एचओ:ओएसआर & आईआर:ए/10/20 दिनांक 10-12-2002	04-01-2003
14.	बीसीसी:एचआरएम:98 दिनांक 20-02-2006	07-04-2006
15.	एचओ:ओएसआर & आईआर:ए 10:150 दिनांक 27-11-2006	02-01-2007
16.	अधिसूचना दिनांक 23-12-2010	22-01-2011
17.	एचओ:एचआर-ओपीएस:ओएसआर&आईआर:282 दिनांक 15-11-2017	12-12-2017
18.	बीसीसी:एचआरएम:ईएक्सई:112/274 दिनांक 31.03.2020	31-03-2020
19.	एचओ:एचआरएम:116:2714 दिनांक 28.11.2024	29-11-2024

विवरणात्मक ज्ञापन

इन विनियम में दिए गए पूर्वव्यापी प्रभाव इस संबंध में संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए विशिष्ट अधिदेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ और बैंकों के अधिकारी संघ के बीच हस्ताक्षरित समझौते और संयुक्त नोटों की सहमत नियम व शर्तों के अनुसार हैं। अतः इस तरह के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

BANK OF BARODA

NOTIFICATION

Mumbai, the 14th July, 2026

Ref: HO:HRM:118:1324.— In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Bank of Baroda in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, except as respect things done or omitted to be done in pursuance of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, letter number 4/2/1/2022-IR, dated the 13th March, 2024, on and from the 1st November, 2022 till the date of publication of this notification in the Official Gazette, hereby makes the following regulations further to amend the Bank of Baroda (Officers') Service Regulations, 1979, namely: -

- (1) These regulations may be called the Bank of Baroda (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Bank of Baroda (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3, for clauses (f), the following clause shall be substituted, namely: -
“(f) ‘Family’ of an officer employee for the purposes of medical facilities and for the purpose of leave fare concession, shall mean:

- (i) the officer employee's spouse;
- (ii) wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children);
- (iii) wholly dependent physically or mentally challenged brothers or sisters with 40 percent or more disability;
- (iv) widowed daughters and dependent divorced or separated daughters;
- (v) sisters including unmarried or divorced or abandoned or separated from husband or widowed sisters;
- (vi) parents wholly dependent on the employee:

Provided that in the case of physically or mentally challenged children, irrespective of age, they shall be construed as dependents even after their marriage subject to fulfilling the income criteria for dependent.

Explanation 1. - The expression "wholly dependent family member" shall mean such member of the family having a monthly income not exceeding Rs.18,000/- and if the monthly income of one of the parents exceeds Rs.18,000/- or the aggregate of monthly income of both the parents exceeds Rs. 18,000/-, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer employee.

Explanation 2. -For the purposes of medical expenses reimbursement scheme, and Leave Fare Concession, for all officer employees, any two of the dependent father, mother, father-in-law, mother-in-law shall be covered. The officer employee will have the choice to substitute either of the dependents, or both, once in a calendar year.

Explanation 3. -This definition of shall be effective from the 1st April, 2024 and for the calendar year 2024, for the purpose of medical insurance scheme or policy and the revised monthly income criteria of dependents shall be effective from the 1st November, 2024."

3. In regulation 4 of the said regulations, -

(a) the *Explanation* to sub-regulation (7) shall be omitted;

(b) for sub-regulations(9) and (10), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

"(9) On and from the 1st November, 2022, the scales of pay specified against each grade shall be as under:

(a) Top Executive Grade

Scale VIII = Rs. 253000 - 9000/4 - 289000

Scale VII = Rs. 156500 – 4340/4 – 173860

Scale VI = Rs. 140500 - 4000/4 – 156500

(b) Senior Management Grade

Scale V = Rs. 120940 – 3360/2 – 127660 – 3680/2 - 135020

Scale IV = Rs. 102300 – 2980/4 – 114220– 3360/2 – 120940

(c) Middle Management Grade

Scale III = Rs. 85920-2680/5– 99320 - 2980/2 - 105280

Scale II = Rs. 64820–2340/1 - 67160 -2680/10 - 93960

(d) Junior Management Grade

Scale I = Rs.48480-2000/7- 62480-2340/2-67160-2680/7-85920.

Explanation. - Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on the 31st October, 2022 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub-regulation as on the 1st November, 2022 on stage-to-stage basis, that is, on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual, except where provided otherwise.

(10) Nothing in sub-regulations (1) to (9) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.

(11) On and from the 1st day of November, 2012, officers shall be paid special allowances as under:

Scale I – III - 7.75 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Scale IV – V – 10 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Scale VI – VII - 11 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

(12) On and from the 1st November, 2017, officers shall be paid special allowance as under:

Scale I – III - 16.40 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Scale IV – V - 19 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Scale VI - VIII – 20 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Provided that an Officer in Scale VIII shall be eligible for special allowance with effect from the 31st March, 2020.

(13) On and from the 1st November, 2022, officers shall be paid special allowances as under:

Scale I - 26.50 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Scale II - III - 28.30 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Scale IV - V - 30.50 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Scale VI - VII - 31.50 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Scale VIII - 28.30 per cent. of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Note: The special allowance referred to sub regulations (11) to (13) with applicable dearness allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, such as pension including Defined Contributory Pension System (New Pension Scheme), Provident Fund and Gratuity”.

4. In regulation 5 of the said regulations, -

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely, -

“(1) Subject to the provisions of sub-regulation (9) of regulation 4, on and from the 1st November, 2022, the increments shall be granted subject to the following conditions, namely: -

- (a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulations (9) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;
- (b) one year after reaching maximum in their respective scales, officers in Scale I and Scale II, shall be granted further increments including stagnation increment in the next higher Scale only as specified in clause (c) and (d) below, subject to their crossing the efficiency bar;
- (c) officers in Junior Management Grade Scale I, who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale II in terms of clause (b) after reaching maximum of the higher Scale, shall be eligible for seven stagnation increments for every two completed years of service of which the first two shall be Rs. 2680/- each and the next five shall be of Rs. 2980/- each:

Provided that the officer shall be eligible for the sixth stagnation increment two years after release of fifth stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided further that the officer shall be eligible for the seventh stagnation increment four years after release of fifth stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later;

- (d) officers in Middle Management Grade Scale II, who have moved to scale of pay for Middle Management Grade Scale III in terms of clause (b), after reaching maximum of higher scale, shall be eligible for seven stagnation increments of Rs. 2980/- each for every two completed years of service:

Provided that the officer shall be eligible for the sixth stagnation increment two years after release of fifth stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided further that the officer shall be eligible for the seventh stagnation increment four years after release of fifth stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later;

- (e) officers in substantive Middle Management Grade Scale III that is, those who are recruited in or promoted to Middle Management Grade Scale III shall be eligible for eight stagnation increments for every two years of completed service after reaching the maximum of scale out of which first four stagnation increments shall be of Rs. 2980/- and the next four stagnation increments shall be of Rs. 3360/- each:

Provided that the officer shall be eligible for seventh stagnation increment two years after release of sixth stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided further that the officer shall be eligible for the eighth stagnation increment four years after release of sixth stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later;

- (f) officers in Senior Management Grade Scale IV shall be eligible for five stagnation increments for every two completed years of service after reaching the maximum of scale, of which first stagnation increment shall be of Rs. 3360/- and the next four stagnation increments shall be of Rs. 3680/- each:

Provided that the officer shall be eligible for the third stagnation increment two years after release of second stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided further that the officer shall be eligible for the fourth stagnation increment four years after release of second stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided also that the officer shall be eligible for the fifth stagnation increment six years after release of second stagnation increment or the 1st November 2022, whichever is later;

- (g) officers in Senior Management Grade Scale V shall be eligible for four stagnation increments of Rs. 4000/- each for every two completed years of service after reaching the maximum of scale:

Provided that the officer shall be eligible for the second stagnation increment four years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided further that the officer shall be eligible for the third stagnation increment six years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided also that the officer shall be eligible for the fourth stagnation increment eight years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later;

- (h) officers in Top Management Grade Scale VI shall be eligible for three stagnation increments for every two completed years of service after reaching the maximum scale of pay, out of which first two stagnation increments shall be of Rs. 4000/- each and the third stagnation increment shall be of Rs. 4340/-:

Provided that the officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for first stagnation increment of Rs. 4000/- two years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided further that the officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for second stagnation increment of Rs. 4000/- four years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided also that the Officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for third stagnation increment of Rs. 4340/- six years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later;

- (i) officers in Top Management Grade Scale VII shall be eligible for three stagnation increments of Rs. 4340/- each for every two completed years of service after reaching the maximum of scale:

Provided that the officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for first stagnation increment, two years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided further that the officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for second stagnation increment four years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later:

Provided also that the officer who has already reached the maximum scale of pay shall be eligible for third stagnation increment, six years after reaching the maximum of scale or the 1st November 2022, whichever is later;

Note: The increment as mentioned in clauses (a) to (i) of this sub-regulation shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

Explanation.- Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.”;

- (b) in sub-regulation (2),-

- (i) before the *Explanation*, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that on and from the 1st November, 2022, officers completing Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination (CAIIB-II) shall be eligible for two increments in their scale of pay apart from one increment for completing Junior Associate of Institute of Indian Bankers’ examination (JAIIB) or Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers examination (CAIIB-I):

Provided further that the officers who were in the services of the Bank as on the 1st November, 2022 and have already completed CAIIB II shall be eligible for 2nd additional increment from the 1st November, 2022 or date of passing CAIIB II, whichever is later:

Provided also that in case where an officer, as on the 8th March, 2024, has already acquired or shall acquire hereinafter JAIIB or CAIIB-I or CAIIB (CAIIB II) after reaching top or maximum of the scale of pay (in case of JAIIB or CAIIB), or after reaching the stage which is one stage less than maximum of scale of pay (in case of JAIIB or CAIIB-I or CAIIB II), and has not earned increments, otherwise entitled on account of acquiring such qualification, when there were no increments to provide in the scale of pay of those employees, the stagnation increment in such cases may be advanced by one year or two years, as the case may be.”

(ii) in the *Explanation*, after clause (h) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely: -

“(i) on and from the 1st November, 2022, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the Table, namely: -

Table

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers Part I	Rs.1370/- per month one year after reaching maximum of the Scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(a) Rs.1370/- per month one year after reaching maximum of the Scale. (b) Rs.3425/- per month two years after reaching maximum of the Scale. (c) Rs.5480/- per month three years after reaching maximum of the Scale.

Provided that an officer employee acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay:

Provided further that on and from the 1st day of November, 2022, no Professional Qualification Pay shall be payable to an Officer employee working in Scale VIII.”;

(iii) in the Note, after Clause (v), the following shall be inserted, namely: -

“(vi) officers who were in the services of the Bank as on the 1st November, 2022 and have already completed JAIIB or CAIIB or CAIIB-II and drawing Professional Qualification Pay -II shall be eligible for Professional Qualification Pay -III one year after the release of Professional Qualification Pay-II or 1st November 2022, whichever is later.

(vii) officers who have completed JAIIB (CAIIB-I) or CAIIB (CAIIB-II) and has reached the maximum in the scale of pay on or before the 1st November, 2022 and has not received the 1st stagnation increment on or before the 1st November, 2022, shall be eligible for Professional Qualification Pay-I on and from the 1st November, 2022 and release of subsequent instalment of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of Professional Qualification Pay I under this clause.”;

(c) in sub-regulation (3), -

(i) the Note after clause (g) shall be omitted;

(ii) after clause (h), the following shall be inserted, namely:-

“(i) On and from the 1st November, 2022, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:-

Table

Increment Component (Rs.)	Dearness Allowance as on the 1 st November, 2022 on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
(1)	(2)	(3)
2680	200	2880
2980	222	3202
3360	250	3610
3680	274	3954
4000	298	4298
4340	323	4663
9000	669	9669

Note:

- (i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (3) of the Tables in clauses (b), (c), (d), (e), (f), (g) (h) and (i) of this sub-regulation shall be payable to those officers employees who are provided with bank's accommodation.
- (ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (1) and (2) of the aforesaid Table under clause (i) and House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) and (9) of regulation 4 is earned;
- (iii) Only officers who are in the service of the Bank on or before the 1st November, 1993 shall be eligible for Fixed Personal Pay one year after reaching the maximum scale of pay, they are placed.
- (iv) On and from the 1st November, 1999, there shall be no change in the schedule of release of professional qualification pay as in clause (c) of the *Explanation* to sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any installment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after the 1st November, 1999 it shall be released to the officer on and from this date and second installment of Professional Qualification Pay, if any, shall be released as on the 1st November, 2000.

- (v) The increment component of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.
 - (vi) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) and (i) of this sub-regulation, one year after reaching the maximum of the scale.”;
5. In regulation 21 of the said regulations, -
- (a) in sub-regulation (6), in the *Explanation*, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-
“(b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in clauses (c), (d), (e), (f), (g), (h) and (i) to the *Explanation* in sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance.”
 - (b) after sub-regulation (7), the following sub-regulation (8) shall be inserted, namely: -
“(8) On and from the 1st November, 2022, -
 - (a) Dearness Allowance shall be payable at 1 per cent. of pay per percentage point of Index.
 - (b) Dearness Allowance in the above manner shall be paid for every variation of rise or fall over 123.03 points in the quarterly average of the All India Consumer Price Index (CPI) for Industrial Workers Base

2016=100. 0.01percentage change in Dearness Allowances on pay for change in every second decimal place of CPI 2016 over 123.03 points.

- (c) The change in the Dearness Allowance rate will be released on a quarterly basis on 1st May, 1st August, 1st November and 1st February based on the following, namely: -

Dearness Allowance release date	Quarterly average of CPI points of the months	Applicable for the month
1 st May	January, February and March	May, June and July
1 st August	April, May and June	August, September and October
1 st November	July, August and September	November, December and January
1 st February	October, November and December	February, March and April

- (d) There shall be no ceiling on Dearness Allowance.

- (e) While working out quarterly average, only first two decimals will be considered.” ;

6. In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulation (1), the following sub-regulations shall be substituted, namely: -

“(1) On and from the 1st November, 2022, -

- (a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 0.35 per cent. of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;
- (b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following Table, namely: -

Table

Serial. Number.	Place of work	House Rent Allowance
(1)	(2)	(3)
1.	Major “A” Class Cities and Project Area Centres in Group A	10.0% of Pay
2.	Other places in Area I and Project Area Centres in Group B and State of Goa	9.0% of Pay
3.	Other places	8.0% of Pay:

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 0.35 per cent. of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent. of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (3) of the above Table.

Note:- The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall be restricted to 150 percent of House Rent Allowance as hitherto.”.

7. In regulation 23 of the said regulations, -

- (a) for sub-regulations (1) and (2), the following sub-regulations shall respectively be substituted, namely:—

“(1) On and from the 1st November, 2022, if an officer is serving in a place mentioned in column (2) of the Table below, a city compensatory allowance at the rate mentioned in column (3) thereof against that place shall be payable.

Table

Serial. Number	Places	Rate
(1)	(2)	(3)
1.	Places in Area 1 and above and in the State of the Goa	Rs. 2300/- per month
2.	Places with population of five lakhs and over and state capitals and Chandigarh, Puducherry and Port Blair	Rs. 1900/- per month.

(2) On and from the 1st November, 2022, the rates of special areas allowances shall be as specified in the Schedule to these regulations:

Provided that where at any of the places indicated in column (1) of the Schedule, Hill and Fuel Allowance as provided under sub-regulation (10) is also payable, then the officer shall be eligible to draw only higher of the two allowances and not both:

Provided further that of such higher of the two allowances is less than the aggregate of Special Allowance and Hill and Fuel Allowance drawn by the officer on 31st December 1989, then such difference shall be protected as Personal Allowance till such time the officer remains at that place.”;

- (b) for sub-regulations (4), (5), (6) and (7), the following sub-regulations shall respectively be substituted, namely: —

“(4) On and from the 1st April, 2024, if an officer is transferred from one place to another in the middle of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs.2500/- per month per child with a maximum upto two children, from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year:

Provided that such allowance shall cease to be payable if all the children cease studying at the former place.

(5) On and from the 1st April, 2024, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.7500/- per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank’s service at that place:

Provided that where such officer is deputed to an organisation which is located at the same place or to the training establishment not owned by the Bank where he was posted immediately prior to his deputation or to the training establishment not owned by the Bank, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent. of his pay subject to a maximum of Rs.3750/- per month:

Provided further that where an officer is deputed to another office or branch within the same municipal limits or urban agglomeration, in Metro or Major ‘A’ class cities where the distance of such deputation is 20 kilometers and more from the parent branch or office, he shall be eligible for halting allowance as provided in sub-regulation (4) of regulation 41;

(6) On and from the 1st April, 2024, if an officer is required to officiate in a post in a higher scale for a continuous period of not less than four days at a time or an aggregate of four days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 15 per cent. of his Basic pay, pro-rata for the period for which he officiates and officiating allowance will rank as pay for the purposes of Provident Fund and Pension only:

Provided that, where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorisation of posts under regulation 6, he shall not be eligible for the Officiating Allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorisation takes effect.

(7) On and from the 1st April, 2024, an officer shall be entitled for a closing allowance of Rs.1500/- per quarter for each of the closing.”;

- (c) for sub-regulations (10), (11), (12) and (13) the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

“(10) On and from the 1st November, 2022, an officer shall be eligible for the Hill and Fuel Allowance as specified in the Table below, namely: -

Table

Serial. Number	Place	Rate
(1)	(2)	(3)
1.	Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs.1450/- per month
2.	Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2.5% of pay subject to a maximum of Rs.1900/- per month
3.	Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.3750/- per month;

(11) On and from the 1st November, 2022, an officer shall be eligible for Learning Allowance of Rs. 850/- per month along with Dearness Allowance thereon.

Note: The Learning Allowance with applicable Dearness Allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, that is, Pension including Defined Contributory Pension Scheme (New Pension Scheme), Provident Fund and Gratuity.

(12) On and from the 1st November, 2022, an officer shall be eligible for a Fixed Location Allowance of Rs.1200/- per month, who are posted in areas other than the areas that are eligible for City Compensatory Allowance. This Fixed Allowance shall not be reckoned for payment of Dearness Allowances, superannuation benefits, that is, pension including Defined Contributory Pension Scheme (New Pension Scheme), Provident Fund and Gratuity.

(13) (a) From the financial year 2023-24, Performance Linked Incentive (PLI) shall be payable to all officer employees based on the metrics put in place by the Competent Authority of the Bank as per their priorities from the following select parameters:

- (i) Current Account and Savings Account;
- (ii) Non-Performing Assets;
- (iii) Special Mention Account;
- (iv) Non – interest income;
- (v) Total Business;
- (vi) Profitability;
- (vii) Return on Assets or Return on Equity;
- (viii) Government Schemes.

(b) The Performance Linked Incentive amount shall be payable in 0-15 (maximum) number of days of pay (Basic + Dearness Allowance) depending on the metrics put in place by the Competent Authority as mentioned in clause (a) above.”.

8. In regulation 24 of the said regulations,-

- (a) for sub-regulation (1) the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(1) On and from the 1st November 2022, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer’s own certificate of the officer of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:-

Table

Serial Number	Grade	Maximum limit of reimbursement
(1)	(2)	(3)
1.	Junior Management and Middle Management Grade	Rs.13000/- per annum or the amount incurred whichever is less
2.	Senior Management and Top Executive Grade	Rs.15400/- per annum or the amount incurred whichever is less

Note 1: An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above,

Note 2: For the calendar year 2022, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November, 2022 and December, 2022.” ;

(b) after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

“(4) All officer employees shall also be eligible for reimbursement of Rs. 500/- per year towards eye check-up.”.

9. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), on and from the 1st November, 2022, it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, a sum equal to 0.35 per cent. of the Basic Pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.075 per cent. of Basic Pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that where such residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.”.

10. In regulation 31 of the said regulations, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that where the Sanctioning Authority refuses or postpones the leave of the officer, it shall record the reasons for the same in writing.”.

11. In regulation 32 of the said regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

“(3) On and from 1st April, 2024, an officer employee shall be eligible to avail two days casual leave for half-a day on four occasions in a year out of which two occasions shall be in the morning and two occasions in the afternoon:

Provided that casual leave under this category shall be availed after applying twenty-four hours in advance:

Provided further that at the time of carrying over the balance in casual leave to unavailed casual leave account, the fraction in the balance, if any, shall be ignored.”.

12. In regulation 33 of the said regulations, -

- (a) for sub-regulations (4) and (5), the following sub-regulation shall respectively be substituted, namely:-

“(4) On and from the 1st June, 2015, privilege leave may be accumulated upto not more than two hundred and seventy days, except where leave has been applied and it has been refused:

Provided that on and from the 1st April, 2024, encashment of privilege leave shall be restricted upto a maximum of two hundred and fifty-five days:

Provided further that an officer shall also be eligible for encashment of privilege leave at the rate of five days for each calendar year at the time of any festival of his choice and an officer who have already completed fifty-five years of age and above shall be eligible to encash privilege leave at the rate of seven days for each calendar year till his retirement.

(5) An officer desiring to avail of privilege leave shall ordinarily give not less than ten days' notice of his intention to avail such leave, except for the purpose of Leave Fare concession.

Provided that on and from the 1st April, 2024, no such advance notice of ten days shall be required for availing privilege leave for office bearers and Executive Committee members of a registered Trade Union.”;

(b) after sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(7) On and from the 1st April, 2024, for the purposes of calculating privilege leave, all types of leave availed except casual leave and mandatory leave shall be excluded”.

13. In regulation 34 of the said regulations, -

(a) In sub-regulation (1), the following provisos shall be inserted, namely: -

“Provided that on and from the 1st April, 2024, an officer shall be eligible for sick leave at the rate of one month for each year of service:

Provided further that the total number of sick leave (including additional sick leave mentioned in regulation 35) shall not exceed seven hundred and twenty days in the entire service of the officer.”;

(b) after sub-regulations (5), the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

“(6) On and from the 1st April 2024, a single male parent employee may avail sick leave for the sickness of his children of eight years and below subject to production of medical certificate.

(7) On and from the 1st April 2024, a women employee may avail one day sick leave per month without production of medical certificate.

(8) On and from the 1st April 2024, officer employees may avail sick leave for the sickness of their special child of fifteen years of age and below for a maximum period of ten days in a calendar year subject to production of medical certificate.

(9) On and from the 1st April 2024, officer employees of the age of fifty-eight years and above, may avail sick leave towards hospitalization of his or her spouse at a centre other than place of work for a maximum period of thirty days in a calendar year.”.

14. In regulation 36 of the said regulations, in sub-regulation (1), -

(a) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely: -

“(a) A Female officer shall be eligible for maternity leave on substantive pay for a period not exceeding six months on any one occasion and twelve months during the entire period of her service:

Provided that in case of delivery of twins, the period of maternity leave shall be eight months:

Provided further that on and from the 1st April, 2024 in case of delivery of more than two children in one delivery, the period of maternity leave shall be twelve months:

Provided also that maternity leave may be availed combining it with any other kind of leave, except casual leave.” ;

(b) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely: -

“(d) A Female officer may avail leave once during service for legally adopting a child who is below one year of age, for a maximum period of nine months, subject to the following terms and conditions, namely: -

(a) leave will be granted for adoption of only one child;

(b) the adoption of a child should be through a proper legal process and the employee should produce the adoption-deed to the Bank for sanctioning such leave;

(c) the leave shall also be available to biological mother in cases where the child is born through surrogacy.

(d) the leave shall be availed within overall entitlement of twelve months during the entire period of service”

(c) after clause (e), the following clauses shall be inserted, namely: -

“(f) On and from the 1st April, 2024, maternity leave may be availed for in vitro fertility (IVF) treatment subject to production of medical certificate within the overall limit of twelve months.

(g) On and from the 1st April, 2024, special maternity leave may be availed by a female employee upto sixty days in case of a still born or death of the infant within twenty-eight days of birth.”.

15. For regulation 37A of the said regulation may be substituted, namely: -

“37A. Special casual leave and special leave.- (1) With effect from the 1st November, 2020, an officer employee shall be eligible for special casual leave on occasions when the branch where the officer is working or the place where he is residing is affected by curfew, riots, prohibitory orders, natural calamities, floods, and the like.

(2) With effect from the 1st November, 2020, a physically or orthopedically handicapped officer shall be eligible for four days special casual leave.

(3) With effect from the 1st April, 2024, Principal Office bearers of All India officers' Unions or Associations shall be granted special leave upto twenty-five days in a calendar year.

(4) With effect from the 1st April, 2024, officers who are Defense Representatives in Departmental enquiry may avail one day special leave for the purpose of preparing the defense submission of an officer employee.

Provided that such special leave shall be availed for a maximum of ten occasions in a year.

(5) An officer may also be granted special casual leave and any special leave as may be decided by the Board in accordance with the guidelines of the Central Government from time to time.”.

16. After regulation 37A of the said regulations, the following regulation shall be inserted, namely: -

“37B. Bereavement Leave.- An officer employee shall be granted bereavement leave on the demise of the family members (spouse, children, parents and parents-in-law) for such number of days as may be decided by the Board from time to time:

Provided that the intervening holidays will form part of the bereavement leave:

Provided further that the said leave should be availed within a maximum period of fifteen days of the demise:

Provided also that the said leave shall not be considered as “Active service” for the purpose of calculation of privilege leave.”.

17. In regulation 41 of the said regulations, -

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(1) On and from the 1st April, 2024, wherever an officer is required to travel on duty, the following provisions shall apply, namely: -

(a) an officer in Junior Management Grade shall be entitled to travel by AC 1st class by any train including Premium Trains like Rajdhani or Shatabdi or Tejas or Vande Bharat or Amrit Bharat, etc. (except luxury trains):

Provided that such officer may travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(b) an officer in Middle Management Grade shall be entitled to travel by AC 1st Class by any train including Premium Trains as mentioned in clause (a):

Provided that such officer may travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 500 kilometers:

Provided further that such officer may travel by air (economy class) even for shorter distance, if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest;

(c) an officer in Senior Management or Top Executive Grade is entitled to travel by AC 1st Class by any train including premium trains as mentioned in clause (a) above or by air (economy class);

(d) an officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 kilometers;

Provided that when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail, only the rest of the distance should normally be covered by car;

- (e) any other officer may be authorised by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Bank's vehicle;
- (f) an officer of any grade or scale shall be eligible to travel by water transport in deluxe cabin category between places not connected by road or air or rail.;
- (g) an officer shall be eligible for fare by premium trains (except luxury trains).

Note 1: Goods and Services Tax charges levied on train fare shall be over and above the entitlement.

Note 2: In view of prevailing dynamic fare system, the cost of train tickets charged on the date of booking shall be reimbursed.

- (b) in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely: -

“(a) Halting Allowances.- On and from the 1st April, 2024, an officer in the grades or scales set out in column (2) of the Table shall be entitled to *per diem* Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (3) thereof, namely: -

Table

Serial Number	Grades or Scales of officers	Halting Allowance			
		Metro Rs.	Major 'A' Class cities Rs.	Area I Rs.	Other Places Rs.
(1)	(2)	(3)			
1.	Officers in Scale VI & above	4050	2925	2475	2150
2.	Officers in Scale IV & V	3375	2925	2475	2150
3.	Officers in Scale I, II and III	2925	2475	2150	1800;

Provided that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation.- For the purpose of computing Halting allowance, *per diem* shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, *per diem* shall mean a period of not less than eight hours.”.

18. In regulation 42 of the said regulations, -

- (a) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(3) On and from the 1st April, 2024, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely: -

Table

Serial Number	Grade or Scale	Amount
(1)	(2)	(3)
1.	Senior Management and Top Executive (Officers in Scale IV and above)	Rs.50000/-
2.	Junior Management and Middle Management (Officers upto Scale III)	Rs.40000/-

(b) in the sub-regulation (4), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

“Provided that on and from the 1st April, 2024, where no residential accommodation is made available by the Bank to an officer at the new place of posting and where such an officer may incur additional expenses in the process of taking over charge, for reasons beyond his control, the Competent Authority, from the date of joining of such officer at the new place, may on merits consider grant of either lodging and Boarding charges or Halting Allowance for a period of fifteen days or till the time the quarters are made available to him, whichever is earlier.”.

19. For regulation 44 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely: -

“44. Leave Travel Concession.- (1) During each block of four years, an officer shall be eligible for Leave Travel Concession for travel to his place of domicile once in each block of two years:

Provided that he may travel in one block of two years to his place of domicile and in another block of two years to any place in India by the shortest route.

(2) With effect from the 1st April, 2024, alternatively, an officer by exercising an option anytime during a four year block or two year block, as the case may be, surrender and encash his Leave Travel Concession (other than travel to place of domicile) upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled up to a distance of 5,500 kilometers (one-way) for officers in Junior Management Grade Scale I, Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III and 6,500 kilometers (one-way) for officers in Senior Management Grade Scale IV and above:

Provided that an officer opting to encash his Leave Travel Concession shall prefer the claim for himself and his family members only once during the block in which such encashment is availed of and the facility of encashment of privilege leave while availing of Leave Travel Concession is also available while encashing the facility of Leave Travel Concession.

(3) The mode and class by which an officer may avail of Leave Travel Concession shall be the same as the officer is normally entitled to travel on transfer and other terms and conditions subject to which the Leave Travel Concession may be availed of by an officer, shall be as decided by the Board from time-to-time:

Provided that with effect from the 1st April, 2024, an officer in Junior Management Grade Scale I while availing Leave Travel Concession, shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement shall be the actual fare or the fare applicable to AC 1st Class fare by train for the distance travelled, whichever is less and the same rules shall apply when an officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III avails Leave Travel Concession, where the distance is less than 500 kilometers.

(4) Once in every four years, when an officer avails of Leave Travel Concession, he may be permitted to surrender and encash his privilege leave not exceeding thirty days at a time or he may, while travelling in one block of two years to his home town and in other block any place in India, be permitted encashment of privilege leave with a maximum of fifteen days in each block or thirty days in one block and for the purpose of leave encashment all the emoluments payable for the month during which the leave travel concession is availed shall be admissible:

Provided that an officer, at his option shall be permitted to encash one day additional privilege leave for donation to Prime Minister's Relief Fund subject to his giving a letter to the Bank to that effect and authorising the bank to remit the amount to the fund.

(5) Leave Travel concession can be availed independently where both husband and wife are working in the same Bank.

(6) For employees working in North-east States, Leave Travel concession shall begin from Guwahati and the eligible train fare from their place of work to Guwahati shall be additionally paid.

(7) The eligible fare for Andaman and Nicobar Islands to Chennai or Kolkata, Lakshadweep to Kochi, far-flung area branches in Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Jammu and Kashmir or any other areas which are not directly connected by train shall be additionally reimbursed under Leave Travel concession in addition to normal entitlement for the employees working in these areas to the nearest major Railway Station.

(8) Leave Travel concession facility shall be allowed for an escort who accompanies an officer with benchmark disabilities on the journey subject to following conditions, namely: -

- (a) prior approval of the competent authority is obtained on each occasion;
- (b) the nature of physical disability of the officer is such as to necessitate an escort for the journey and in case of doubt, the decision of the head of the Department or Controller shall be final;

- (c) the officer with such benchmark disabilities does not have an adult family member as dependent to accompany him;
- (d) the officer with such benchmark disabilities and the escort shall avail of the concession, if any, in the Rail or Bus fare as might be extended by Railways or State Roadways authorities in such cases; and
- (e) any other person who is entitled to Leave Travel concession as dependent does not accompany the officer with such benchmark disabilities on the journey.

(9) Where an officer has applied for Leave Travel concession or Leave in advance and has also booked the tickets and the Leave Travel concession is declined or deferred by the management, the cancellation charges shall be reimbursed by the Bank.

(10) Where an officer has applied for Leave Travel concession or leave as per stipulated time and the same is sanctioned and when advance booking of train tickets is not possible, tickets purchased under Tatkal or Premium tatkal will be reimbursed.”.

20. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely: -

“SCHEDULE

[See sub-regulation (2) of regulation 23]

On and from the 1st November, 2022, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified, either wholly or partially, as specified in the Table below, namely: -

Table

Special Area Allowance

Serial Number	Place	Allowances (in Rs.)	
		Pay below Rs.48,481/-	Pay above Rs. 48,481/-
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mizoram		
	(a) Chhimtuipui District and areas beyond 25 kms from Lunglei Town in Lunglei District.	4100	5300
	(b) Entire Lunglei District excluding areas beyond 25 kms from Lunglei town	4100	5300
	(c) Entire Aizawl District	2700	3400
2	Nagaland	4100	5300
3	Andaman and Nicobar Islands		
	(a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	4100	5300
	(b) South Andaman (including Port Blair)	4100	5300
4	Sikkim	4100	5300
5	Lakshadweep Islands	4100	5300
6	Assam	1000	1200
7	Meghalaya	1000	1200
8	Tripura		
	(a) Difficult areas of Tripura	4100	5300
	(b) Throughout Tripura except Difficult areas	2700	3400
9	Manipur	2700	3400
10	Arunachal Pradesh		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	4100	5300

	(b) Throughout Arunachal Pradesh except Difficult areas	4100	5300
11	A.- Union Territory of Jammu and Kashmir		
	(1) Kathua District: Niabat Bani, Lohi, Malhar and Machhodi	4100	5300
	(2) Udhampur District:		
	(a) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, Thakrakote and Nagote	4100	5300
	(b) All Areas in Mahore tehsil other than those included in (c) below	4100	5300
	(c) Areas upto Goel from Kamban Side and Areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre	4100	5300
	(3) Doda District: Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kashmir Tehsil	4100	5300
	(4) Baramulla District:		
	(a) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and Keran Illaqa	4100	5300
	(b) Matchill	4100	5300
	(5) Poonch and Rajouri District: Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts	2700	3400
	(6) Areas not included in (1) to (5) above, but which are within the distance of 8 kms. from the Line of Actual Control (LOC) or at places which may be declared as qualifying for Border Allowance from time to time by the State Government for their own staff.	2700	3400
	B.- Union territory of Ladakh: Leh District: Noyama and Nobre Zaskar All other places in the District	4100	5300
12	Himachal Pradesh		
	(1) Chamba District		
	(a) Pangi Tehsil, Following Panchayats and Villages in Bharmour Tehsil: Panchayats: Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tunda Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata	4100	5300
	(b) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in (a) above	4100	5300
	(c) Jhandru Panchayat in Bhartiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper)	2700	3400
	(2) Kinnaur District		

	(a) Asrang, Chitkul and Hango Kuno or Charang Panchayats; 15/ 20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above	4100	5300
	(b) Entire District other than Areas included in (a) above	4100	5300
	(3) Kullu District		
	(a) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	4100	5300
	(b) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District excluding outer Saraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burao of Tehsil Nirmand)	2700	3400
	(4) Lahaul and Spiti District: Entire area of Lahaul and Spiti	4100	5300
	(5) Shimla District		
	(a) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chandi-Branda	4100	5300
	(b) Dodra-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghori Chaibis of Pargana Sarahan	4100	5300
	(c) Chopal Tehsil (i) Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, (ii) Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, (iii) Pargana Barabis, (iv) Kasba Rampur and Ghori Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, (d) Shimla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu)	2700	3400
	(6) Kangra District:		
	(a) Areas of Bara Bhangal and Chhota Bhangal	4100	5301
	(I) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town: (a) Women's ITI, Dari, (b) Mechanical Workshop, Ramnagar, (c) Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, (d) CRSF Office at lower Sakoh, (e) Kangra Milk Supply Scheme, Dugar, (f) HRTC Workshop, Sadher, (g) Zonal Malaria Office, Dari,	2700	3400

	(h) Forest Corporation Office, Shamnagar, (i) Tea Factory, Dari, (j) I.P.H. Sub- Division, Dari (k) Settlement Office, Shamnagar, (l) Binwa Project, Shamnagar, (II) Palampur Town, including Himachal Pradesh Krishi Vishwa Vidyalaya (HPKVV) Campus at Palampur and following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town: (a) H.P. Krishi Vishwavidyalaya Campus, (b) Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, (c) Sericulture Office/Indo- German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, (d) Electrical Sub-Division, Lohna, (e) D.P.O. Corporation, Bundla, (f) Electrical HPSE Division, Ghuggar		
	(7) Mandi District:		
	Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in Thunag Tehsil: Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjheli, Jaryar, Johar Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Following Panchayats of Dharampur Block: Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja	2700	3400
	(8) Sirmaur District: (a) Following Panchayats of (i) Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil); (ii) Bharog Bheneri (Paonta Tehsil); (iii) Birla (Nahan Tehsil); (iv) Dibber (Pachhad Tehsil); and (v) Thana Kasoga (Nahan Tehsil) (b) Thansgiri Tract	2700	3400
	(9) Solan District: Mangal Panchayat.	2700	3400

	(10) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in (1) to (9) above	1000	1200
13	Uttarakhand: Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat Districts	4100	5300
14	West Bengal: South 24 Parganas District Sunderban areas (south of Dampier Hodge's line), namely, Bhagatush Khali (Rampura), Kumirmari (Bagna), Jhinga Khali, Sajnakhali, Gosaba, Amlamathi (Bidya), Canning, Kultali, Piyali, Nalgaraha, Raidighi, Bhanchi, Pathar Pratima, Bhagabatpur, Saptamukhi, Namkhana, Sikarpur, Kakdwip, Sagar, Mousini, Kalinagar, Haroa, Hingalganj, Basanti, Kuemari, Kultola, Ghushighata (Kulti)	1000	1200''

SHAILENDRA SINGH, Chief General Manager (Hrm & Marketing)

[ADVT.-III/4/Exty./222/2026-27]

Note: The Bank of Baroda (Officers') Service Regulations, 1979 were published in the Gazette of India and subsequently amended vide the following notifications published in the Gazette of India, Part III Section 4, namely:-

Serial number	Gazette notification number	Date of publication in the Official Gazette
1.	HO:STF:A:10/13:455 dated 07-03-1988	26-03-1988
2.	HO:STF:A:10/13:456 dated 07-03-1988	26-03-1988
3.	HO:STF:A:10/15:73 dated 21-01-1989	25-02-1989
4.	HO:STF:A:10/15:267 dated 01-03-1989	01-04-1989
5.	HO:STF:A:10/10:792 dated 10-05-1990	16-06-1990
6.	HO:OSR&IR:A/10/14:1030 dated 21-07-1993	25-09-1993
7.	HO:OSR&IR:A/10/16:1029 dated 21-07-1993	25-09-1993
8.	HO:OSR&IR:A/10/9:657 dated 05-06-1993	24-07-1993
9.	HO:OSR&IR:A/10/14:704 dated 30-04-1994	16-07-1994
10.	HO:OSR&IR:A/6/9:2828 dated 17.01.1997	22-02-1997
11.	HO:OSR&IR:A/12/9:2902 dated 11-12-1999	24-01-2000
12.	HO:OSR&IR:A/10/18:1057 dated 15.05.2000	29-07-2000
13.	HO:OSR&IR:A/10/20 dated 10-12-2002	04-01-2003
14.	BCC:HRM:98 dated 20-02-2006	07-04-2006
15.	HO:OSR & IR :A:10:150 dated 27-11-2006	02-01-2007
16.	Notification dated 23-12-2010	22-01-2011
17.	HO:HR-OPS:OSR&IR:282 dated 15-11-2017	12-12-2017
18.	BCC:HRM:EXE:112/274 dated 31.03.2020	31-03-2020
19.	HO:HRM:116:2714 dated 28.11.2024	29-11-2024

EXPLANATORY MEMORANDUM

These regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.